(No.1) That at page 4, line 14, *for* the words, "the Central Government may make", the words, "The Central Government may, with the prior approval of both the Houses of Parliament, make,", be *substituted*.

*The question was put and the motion was negatived.*

*Clause 11 was added to the Bill.*
*Clause 12, the First Schedule, the Second Schedule and the Third Schedule were added to the Bill.*
*Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shri Kinjarapu Rammohan Naidu to move that the Bill be passed.

SHRI KINJARAPU RAMMOHAN NAIDU: Sir, I move:

"That the Bill be passed."

*The question was put and the motion was adopted.*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, we shall take up the "Tribhuvan" Sahkari University Bill, 2025. Shri Murlidhar Mohol to move a motion for consideration of the "Tribhuvan" Sahkari University Bill, 2025.

**श्री जयराम रमेशः** सर, कैबिनेट मंत्री कहां हैं?

**श्री उपसभापतिः** अनेक कैबिनेट मंत्री बैठे हैं।

**The "Tribhuvan" Sahkari University Bill, 2025**

**सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल):** महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि इंस्टीट्यूट आफ रूरल मैनेजमेंट, आणंद, "त्रिभुवन" सहकारी यूनिवर्सिटी के रूप में ज्ञात विश्वविद्यालय की स्थापना करने और उसे राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करने; सहकारी क्षेत्र में तकनीकी और प्रबंधन शिक्षा तथा प्रशिक्षण प्रदान करने; सहकारी अनुसंधान और विकास की प्रोन्नति करने तथा 'सहकार से समृद्धि' के दर्शन को चरित्रार्थ करने के क्रम में इसमें वैश्विक

श्रेष्ठता के मानकों को प्राप्त करने और संस्थाओं के तंत्र के माध्यम से देश में सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए, और संस्थान को विश्वविद्यालय के एक स्कूल के रूप में घोषित करने और उससे संबद्ध तथा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर, लोक सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाए।"

**श्री उपसभापतिः** क्या आप इस बिल पर कुछ बोलना चाहते हैं?

**श्री मुरलीधर मोहोल**: सर, बाद में।

*The question was proposed.*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Motion moved. I shall now call upon the Members whose names have been received for participation in the discussion. Shri Digvijaya Singh.

**श्री दिग्विजय सिंह** (मध्य प्रदेश)ः माननीय उपसभापति महोदय, हम चाहते थे कि माननीय गृह मंत्री जी यहां पर मौजूद हों, क्योंकि यह उन्हीं के कार्यक्षेत्र का मसला है और उन्हीं के विवेक एवं सुझाव पर शायद मंत्रालय कृषि विभाग से लेकर गृह विभाग को सौंपा गया है। हम माननीय मंत्री जी और सरकार के आभारी हैं कि ...(**व्यवधान**)...

**श्री उपसभापतिः** प्लीज़, शांति बनाए रखें।

**श्री दिग्विजय सिंहः** सहकारी विश्वविद्यालय के बिल का नामकरण एक ऐसे वरिष्ठ, तत्कालीन सहकारिता के कांग्रेस के कार्यकर्ता, आदरणीय श्री त्रिभुवनदास पटेल जी के नाम पर रखा है, जिन्होंने सरदार वल्लभभाई पटेल की प्रेरणा से और V. Kurien साहब के सहयोग से इस देश में श्वेत क्रांति की अगुवाई की।

माननीय उपसभापति महोदय, मैं 2014 के पहले की बात कर रहा हूं। उसके बाद क्या हुआ है, इसकी जानकारी शायद मंत्री जी देंगे।

महोदय, लोकतंत्र में सरकार की नीयत उसकी नीति, नियम और कानूनों में झलकती है। इनके 11-12 साल के कार्यकाल में तीन बिंदु साफ झलकते हैं। पहला- हर नीति में, नियम में, कानून में इनकी नीयत पूंजीवादी व्यवस्था के पक्ष में झलकती है। दूसरा, सत्ता के केन्द्रीयकरण में और राज्यों के अधिकारों को हथियाने में इनकी नीयत झलकती है। तीसरा, आप जानते हैं कि हर बात में सांप्रदायिक कटुता फैलाकर वे अपनी नीयत प्रदर्शित करते हैं।

महोदय, गुजरात के गांव कैरा में दूध उत्पादकों ने आंदोलन किया। उस समय Polson butter के लिए वहां से दूध ले जाया जाता था। किसानों ने आंदोलन किया कि आप कम भाव में दूध लेते हैं और मुंबई मिल्क स्कीम को महंगा बेचते हैं। वे सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास आए। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कहा कि दूध सहकारी समिति का गठन करो और मोरारजी भाई

देसाई को कहा कि आप इनका सहयोग कीजिए। वर्ष 1946 में अमूल सहकारी समिति प्रारंभ हुई। यह एक ऐसा उदाहरण है, जो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच की खाई को पाटता है। सामान्य तौर पर आज की व्यवस्था में बिचौलिए और प्रोसेसिंग के बाद किसान को उनकी उपज का केवल 30-40 प्रतिशत ही मिल पाता है, लेकिन अमूल एक ऐसी संस्था है, जिसका 80 प्रतिशत भाग उपभोक्ताओं से आता है, वह किसानों के पास जाता है। यही शक्ति है सहकारिता की। इसमें यही कारण है, जिसकी वजह से भारतीय संविधान में आर्टिकल 243 सहकारिता के ऊपर संविधान में रखा गया है। सरदार पटेल ने कहा था कि "There is no other instrument as potentially powerful and full of social purpose as the cooperative movement."

महोदय, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि सरदार पटेल ने कहा था कि सहकारिता केवल आर्थिक गतिविधि नहीं है, बल्कि वह एकता की, न्याय की और समरसता की एक अलग प्रकार की जीवनशैली है।

[**उपसभाध्यक्ष (श्रीमती धर्मशीला गुप्ता)** *पीठासीन हुईं।*]

इसी सहकारिता के बारे में उन्होंने कहा था कि यह भारत को शक्तिशाली बनाएगा और अखंड रहेगा और आर्थिक और सामाजिक विकास के माध्यम से इसे आगे बढ़ाएगा। इसलिए संविधान में इसे राज्यों की सूची में रखा गया है। देखने में यह आ रहा है कि लगातार राज्यों के अधिकारी, हमारा राज्यों का हाउस है और इस राज्यों के हाउस में लगातार राज्यों के अधिकार को धीरे-धीरे कम किया जा रहा है। माननीय मंत्री जी यहां उपस्थित नहीं हैं। अगर अमित शाह जी, आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल के रूप में दूसरा सरदार गुजरात का बनना है, तो आप कम से कम उनके विचारों को अंगीकार कीजिए। सहकारिता के माध्यम से, जनता के किसानों के माध्यम, उपभोक्ताओं के माध्यम से ...(**व्यवधान**)... जी, मैं वही कह रहा हूं कि आपको करना है, तो उनके विचारों का पालन कीजिए, लेकिन इन्होंने राज्यों का अधिकार छीना है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आज केन्द्र सरकार ने सहकारी मंत्रालय बनाया। पूर्व में यह मंत्रालय कृषि विभाग के साथ था। पहले यह Ministry of Agriculture and Cooperation हुआ करती थी, लेकिन किस उद्देश्य के साथ, किस मंशा के साथ माननीय प्रधान मंत्री जी ने सहकारिता को अलग किया... और सहकारिता को कृषि से अलग करके गृह मंत्रालय के साथ जो जोड़ा गया है, उसमें क्या राज छिपा है, मैं उसके बारे में आपसे कह नहीं सकता हूं। ...(**व्यवधान**)...

महोदया, मैं आज इस मामले में आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि ...(**व्यवधान**)... जोशी जी, इसमें क्या राज छिपा है, इसके बारे में आप पता नहीं लगा पाएंगे, यह गुजरात का मामला है। मैं अनुरोध करना चाहता हूं, आप देख रहे हैं ...(**व्यवधान**)...

**उपसभाध्यक्ष (श्रीमती धर्मशीला गुप्ता)**: माननीय सदस्य, कृपया बैठ जाइए।

**श्री दिग्विजय सिंह**: महोदया, I am not yielding. इस बिल के माध्यम से कोऑपरेटिव का कॉर्पोरेटाइटेशन हो रहा है। यानी कि जो कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री है और कोऑपरेटिव सहकारिता

है, वह सहकारिता किसान और मजदूरों के हाथ से निकालकर उद्योगपतियों के हाथ में सौंपने का प्रयास है।

महोदया, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि भारत और विश्व स्तर पर हुए सहकारिता आंदोलनों में हमेशा से समाजवादी विचारधारा निहित रही है। यह श्रमिक केंद्रित आंदोलन रहा है और श्रमिकों के नेतृत्व में चलता है। केपिटलिज्म, कॉरपोरेट्स और सहकारिता में यही अंतर है। केपिटलिज्म में कॉरपोरेट्स पूंजी से मजदूर लेते हैं और सहकारिता में मजदूरों से पूंजी इकट्ठी करके मजदूरों को उनका हक दिया जाता है। कॉरपोरेट्स और कोऑपरेटिव के बीच में यही फर्क है।

महोदया, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारे संविधान के अनुसार कोऑपरेटिव सोसायटीज़ में हर पाँचवें साल चुनाव होने चाहिए। उनके लिए 6 महीने के एक्सटेंशन के बाद किसी भी हालत में चुनाव कराना आवश्यक है। लेकिन आप देख रहे हैं और मुझे मालूम है कि अनेक प्रदेशों में, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकारें हैं, वहाँ पर सहकारी समितियों के चुनाव नहीं कराए जाते, बल्कि वहाँ पर प्रशासक नियुक्त किया जाता है। महोदया, वे प्रशासक के माध्यम से सहकारी समितियों में जैसा चाहते हैं, वैसा मनमाना निर्णय कराते हैं।

महोदया, मैं और राज्यों के बारे में तो ज्यादा बात नहीं जानता हूं, लेकिन मध्य प्रदेश के बारे में कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में 4,536 PACS हैं, यानी Primary Agricultural Credit Societies हैं। उनमें से 3,800, यानी जो 80 प्रतिशत Primary Agricultural Credit Societies हैं, वे आज पूरी तरह से overdue हो चुकी हैं, भारी घाटे में हैं और वहाँ पर चुनाव भी नहीं हो रहे हैं। महोदया, इसी प्रकार से 38 जिला सहकारी बैंक्स में से लगभग 13 जिला सहकारी बैंक्स की हालत यह है कि वे अपने सदस्यों को 2,000 रुपये भी नहीं दे सकतीं।

महोदया, इसी प्रकार से अन्य घोटालों का भी अंबार है। शिवपुरी जिला सहकारी बैंक में 100 करोड़ रुपये का गबन हुआ, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, ग्वालियर में 25 करोड़ रुपये का गबन हुआ, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। माननीय उपसभाध्यक्ष महोदया, इतना ही नहीं अनेक सहकारी संस्थाओं में 20 साल से सहकारी समिति के चुनाव नहीं हुए और वहाँ पर प्रशासक को बिठा रखा है। माननीय मंत्री जोशी जी, आप इस मामले में गृह मंत्री जी को कम से कम इतना बता दीजिए, ..(**व्यवधान**)..सहकारिता मंत्री जी को बता दीजिए कि आप सहकारिता के मंत्री हैं, इसलिए कृपा करके कम से कम राज्यों में सहकारिता की क्या हालत है, उसका पता लगा लीजिए। पाँच साल में चुनाव होना चाहिए — ऐसा संविधान में प्रावधान है, लेकिन मध्य प्रदेश की डबल इंजन सरकार ने उसमें भी कानून परिवर्तन करके कह दिया कि चुनाव न हों, तो न हों, लेकिन अनंतकाल तक चुनाव स्थगित करने का अधिकार दे दिया और अनंतकाल तक प्रशासक को बैठने का अधिकार भी दे दिया। ये हैं सहकारिता के हालात इस देश में!

महोदया, माननीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी, जो सरदार पटेल का एक दूसरा रूप बनना चाहते हैं, मैं इसी तरह से कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के cooperative apex bank के प्रबंध संचालक पर गबन की शिकायत हुई थी, 12 बार प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, यानी पीएमओ ने राज्य सरकार को लिखकर भेजा कि इस पर कार्रवाई कीजिए, लेकिन राज्य सरकार ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। यह डबल इंजन सरकार की हालत है! कुरियन साहब ने पूरी तरह से

अमूल का प्रबंधन किया और उसे स्टेटस दिया। उन्होंने IRMA का गठन इसलिए किया, क्योंकि वहां पर ऐसे मैनेजर्स, ऐसे कार्यकर्ताओं, ऐसे कर्मचारियों और अधिकारियों की जरूरत थी, जो किसान और मजदूर के हित की बात समझें और किसानों को संगठित करने की क्षमता उनमें पैदा की जाए। NDDB, गुजरात सरकार और अन्य लोगों ने मिलकर संयुक्त प्रयासों से इसका गठन किया। आज इस IRMA जैसे संगठन को हथियाने के लिए यह सहकारी यूनिवर्सिटी बिल लाया गया है, क्योंकि इसमें राज्यों के अधिकारों की बात थी।

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मोटे तौर पर आज इसको दूसरे मैनेजमेंट कोर्सेज के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि जो दूसरे बिजनेस मैनेजमेंट इंस्टिट्यूट्स हैं, उनका सारा concentration और focus उस तरह के मैनेजर और अधिकारी बनने के पक्ष में होता है, जिनसे शेयरहोल्डर्स को ज्यादा मुनाफा हो, ताकि शेयर्स के प्राइसेज बढ़ें। आज कोई भी कॉर्पोरेट मुनाफे को वर्कर्स और employees के साथ शेयर नहीं कर रहा है। IRMA के अंदर जो मैनेजमेंट कोर्सेज हैं, उन पर उसका हमेशा से अधिकार था और उसकी ऑटोनॉमी थी। बिल में कहा गया कि हम ऑटोनॉमी कायम रखेंगे, जबकि केंद्र सरकार के रहते हुए वाइस चांसलर वे अपॉइंट करेंगे, चांसलर वे अपॉइंट करेंगे और गवर्निंग बॉडी के सारे मेंबर्स भी वे अपॉइंट करेंगे, तो ऑटोनॉमी कहां तक रहेगी? तो पूरे तरीके से IRMA को हथियाने के लिए यह यूनिवर्सिटी बिल लाया गया है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि मूल रूप से IRMA अभी तक किसानों के हित में - IRMA जो है, यह सरकार की संस्था नहीं है, बल्कि यह संस्था वहां पर दूध उत्पादकों और किसानों के शेयरहोल्डर्स, मालिकों की वजह से उनके प्रति जिम्मेदार थी, लेकिन अब इस कानून के माध्यम से उनका हक चला जाएगा और जिन्होंने शेयर लिए हुए हैं, उनका अधिकार छीनकर केंद्र सरकार ने अब उस पर कब्जा कर लिया है। माननीय मंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं और आपके माध्यम से अमित शाह जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि कम से कम इसकी फैकल्टी की अपॉइंटमेंट में इस बात का ध्यान रखा जाए कि आप किन्हें वहां पर अपॉइंट करने जा रहे हैं। जैसा कि आपने बताया कि यह ऑटोनॉमस रहेगा, लेकिन उस ऑटोनॉमी में इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि उसमें जो कोर्सेज हों और जो फैकल्टी अपॉइंट हो, उनमें उन लोगों का चयन होना चाहिए, जिनकी सोच और विचारधारा किसानों के हित में हो, जो सहकारिता के पक्ष में हों और जो मजदूरों के पक्ष में हों। सहकारिता आंदोलन की पूरे विश्व में जो कल्पना है, जिसको सरदार वल्लभभाई पटेल ने हमेशा आगे बढ़ाया और वे इसके बड़े नेता रहे हैं। आज आप सरदार वल्लभभाई पटेल की बड़ी-बड़ी मूर्तियां लगाते हैं और उनके नाम से कसम खाते हैं ...**(व्यवधान)**... लेकिन पूरे IRMA को, वहां के सहकारिता आंदोलन को समाप्त करने के लिए यह विश्वविद्यालय कायम किया गया है।

मैं यह भी अनुरोध करना चाहता हूं कि इसके एडमिशन टेस्ट को बिजनेस मैनेजमेंट इंस्टिट्यूट में जो कम्बाइन्ड एडमिशन टेस्ट होता है, उससे अलग रखना चाहिए, क्योंकि जो छात्र यहां पर भर्ती होना चाहते हैं, वे लोग मूल रूप से कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करने के लिए उन इंडियन इंस्टिट्यूट्स ऑफ मैनेजमेंट में एमबीए कोर्सेज़ के लिए जाते हैं।

लेकिन IRMA के लिए अलग से चयन प्रक्रिया होनी चाहिए, अलग से admission test होना चाहिए, जिससे उसी प्रकार के लोग वहाँ पर admission लें, वे ही छात्र उसमें admission

लें, जो गरीबों के बीच में, किसानों के बीच में, मजदूरों के बीच में, slums में, गरीब इलाकों में काम करने की मानसिकता रखते हों। जो अपना भविष्य उनकी सेवा में लगाना चाहते हैं, कम से कम उसी प्रकार के छात्र वहाँ पर प्रवेश लें।

मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि आज IRMA की autonomy कायम रखना अति आवश्यक है। हम नए विश्वविद्यालय की स्थापना का समर्थन करते हैं और इस तथ्य की भी सराहना करते हैं कि आपने इसका नाम हमारे कांग्रेस के एक महान नेता, त्रिभुवनदास पटेल जी के नाम पर रखा, लेकिन इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। आप IRMA को इसमें शामिल किए बिना भी विश्वविद्यालय बना सकते थे, लेकिन आपका जो hidden agenda है, वह hidden agenda है - IRMA को समाप्त करो, किसानों का सहकारी आंदोलन समाप्त करो, तभी जाकर उनका उद्देश्य पूरा होगा। यही उनकी नीयत है, जिसका ज़िक्र मैंने आपसे पहले किया था।

माननीय जोशी जी, मैं आपसे इतना ही अनुरोध करूँगा कि आप हाथ जोड़ कर हमारा प्रार्थना संदेश पहुँचा दीजिए कि वे कम से कम इसे बख्शें और आज भी समय है, IRMA को त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी में से बाहर करें। आप अलग से सहकारी यूनिवर्सिटी बनाइए, अलग से सहकारिता के कोर्सेज़ चलाइए, लेकिन आप कम से कम IRMA को बर्बाद मत करिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

**उपसभाध्यक्ष (श्रीमती धर्मशीला गुप्ता)**: धन्यवाद, माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, श्री नरहरी अमीन। आपके पास 15 मिनट का समय है।

SHRI NARHARI AMIN (Gujarat): [&] Madam Vice Chairperson, I rise in support of the Tribhuvan Sahakari University Bill, 2025. I would like to deliver my speech in Gujarati. The roots of the cooperative movement in the nation were planted prior to independence. Tribhuvan Das Kashibhai Patel of Kheda district was an activist, lawyer, and statesman of the Indian independence struggle. He aligned himself with Mahatma Gandhi and Sardar Vallabhbhai Patel during the struggle for independence. He was the founding figure of the Kheda District Milk Producers Cooperative Union and the Anand Cooperative Movement, earning him the moniker of the father of the cooperative movement in India. Under hon. Sardar Patel's guidance,the Gujarat Co-Operative Milk Marketing Federation, Anand Amul Dairy, and National Dairy Development Board were established in 1946, laying the groundwork for the co-operative movement. Presently, Amul Dairy stands as the largest dairy in India and Asia, serving as a lifeline for countless small and medium farmers. In our nation, the co-operative sector has flourished due to the Government's dedication, with Gujarat

[&] English translation of the original speech delivered in Gujarati.

boasting a rich tradition in this domain. Over the past decade, significant strides have been made by the Government under the leadership of the esteemed Prime Minister, Shri Narendrabhai Modi, in revitalizing cooperative activities, particularly in the rural and agricultural sectors. A dedicated Ministry of Cooperation was established in the Central Government, outlining a comprehensive vision to expand the reach of cooperative endeavors and ensure equitable progress across all states. Aiming to elevate the cooperative movement to new heights, a holistic approach has been adopted. Numerous cooperative entities in the state have long operated under the motto 'No way-out without cooperation'.

Milk cooperatives, Agricultural Produce Market Union, Credit Societies, District Cooperative Banks, and particularly Service Cooperative Societies have conferred a unique identity upon the cooperative sector of Gujarat. Operating in accordance with the cooperative principles, these societies fulfill their societal obligations in a democratic manner while fostering the growth of their members. Amidst the Covid pandemic, our cooperative entities have been at the forefront of service initiatives. Upholding their fundamental values, they have spared no endeavor in assisting individuals during times of crisis. Service Cooperative Societies have not only significantly contributed to the economic progress of the state but have also played a pivotal role in promoting social cohesion. Currently, Gujarat hosts 1 State Government Bank, 18 Central District Cooperative Banks, 10166 Primary Agricultural Credit Societies, 223 Citizen Co-operative Banks, 16091 Milk Societies, 2017 Consumer Cooperative Stores, and 83134 diverse cooperative entities including Agricultural Produce Market Committees and Taluka Cooperative Purchase and Sale Unions. Nationally, there are over 800,000 cooperative societies, encompassing approximately 98% of rural India. Around 30 crore individuals are affiliated with such cooperatives, indicating that one in every five citizens is linked to the cooperative sector in some capacity. Remarkably, a quarter of all cooperative societies worldwide are located in our nation, making a substantial contribution to rural development and economic fortification. Small service cooperative societies engage in a spectrum of activities such as operating local farmer assistance centers, dispensing fertilizers and seeds, managing retail outlets for petrol and diesel, overseeing water resource management, and installing solar panels. The States of Maharashtra and Gujarat have made a huge contribution to the cooperative sector in the entire country. To study the cooperative activities of Maharashtra and Gujarat, cooperative leaders of the country and States as well as cooperative leaders from many countries of the world come to study. Gujarat state has given many national level cooperative leaders; Shambhubhai

Patel, Jayarambhai Patel, Atmaram Patel, Dwarkadas Patel, Shantibhai Patel, Popatlal Vyas, Arvindbhai Maniyar, Parsi Bhatol, Galbabhai Chaudhary, Motibhai Chaudhary and many other cooperative leaders have accelerated cooperative activities from Gujarat. The current Union Home and Cooperation Minister Shri Amitbhai Shah was associated with various cooperative organizations since 1999, the time he was the leader of BJP Yuva Morcha. Respected Amitbhai Shah was the chairman of Asia's largest ADC Bank, which currently has more than 106 branches. He was also the Director in Gujarat State Co-operative Bank for years. Shri Digvijay Singh has left. I want to tell him something. During his speech, he asked, why did the hon. Prime Minister Modiji give the responsibility of the Ministry of Co-operation to Shri Amitbhai Shah. The reason is that Shri Amitbhai Shah was the leader of the BJP Yuva Morcha since 1999. He has a vast experience of the co-operative sector. Beginning from the co-operative activities at the rural level, he has worked at various levels, that is the State and national levels. Shri Amitbhai Shah, who was associated with cooperative activities from a young age, was entrusted with the responsibility of the Minister of Cooperation by the Prime Minister of the country, Shri Narendrabhai Modi. After 70 years of independence, the humane Prime Minister Shri Narendrabhai Modi has made cooperative activities flourish throughout the country and the country develops through cooperative means. Also, to give priority to cooperative activities, the Ministry of Cooperation was created separately in the year 2021 and its responsibility was entrusted to the hon. Shri Amitbhai Shah and in the current five-year period, the work of accelerating cooperative activities in the country is being done by the hon. Home Minister Shri Amitbhai Shah. During this 5 year period, all the co-operative institutions, beginning from the Block level (Taluka level) to the State level, all the Co-operative institutions are prospering under the leadership of BJP leaders. 25 years ago, there was a time all the Co-operative institutions were led by the Congress party. Today, the Congress has ZERO institutions. All the institutions are functioning under the leadership of BJP leaders. People are sure that under the BJP regime and the able guidance of the hon. Minister of Co-operation Shri Amitbhai Shah, the activities in the co-operative sector will prosper more and more. The members of these co-operative societies earn more dividend. Today, in Gujarat, there are many state level co-operative institutions and societies that give 15-20 percent dividend to its members.

During the Congress regime (UPA Government), the Budget of the Ministry of Cooperation was only Rs 122 crore in the year 2013-14. Whereas today, after the setting of the Ministry of Cooperation in the Government led by hon. Amitbhai Shah

and hon. Prime Minister Shri Narendrabhai Modi ji, this Budget has increased to Rs 1183 crore which is nine times more than the UPA Government. To bring flexibility in the working style of cooperative societies, the Government has so far completed the process of computerization of more than 63,000 Primary Agricultural Credit Societies (PACS). The Government has also set a target of computerizing 1851 agricultural banks and Registrar of Co-operative Society offices of the country at a cost of Rs. 225 crore. To realise the vision of "Cooperation for Prosperity", the Ministry of Cooperation, Government of India, has taken various initiatives to revive and strengthen the cooperative sector across the country. Due to these initiatives, the institutions will be strengthened even in those States/Union Territories where the cooperative movement is not in a good condition at present and thus the equitable development of the cooperative institutions/society of the country will be ensured. To increase the penetration of cooperative-based products in the international market, the Ministry of Cooperation has established the "National Cooperative Export Limited", which will focus on exporting cooperative products by reaching out to large markets outside the country. Today, 8863 cooperative institutions in the country have become its members. To make the Primary Agricultural Credit Societies of the country multipurpose and multi-dimensional, "Model Bylaws" have been prepared as a guideline for all the states and provisions have also been made to make its membership more extensive, so that women and SC, ST communities get adequate representation. 32 states of the country have adopted these Bylaws. To strengthen such Primary Agricultural Credit Societies, a "Computerization Project" with a cost of Rs. 2516 crores has been approved and a plan to establish dairy and fisheries cooperatives to make them multipurpose has also been approved. In the next five years, through the coordination of various organizations of the country and various schemes of the Government of India, "the world's largest decentralized grain storage scheme" has also been approved in the cooperative sector. This will reduce the wastage and transportation costs of grains. Farmers will get better prices for their produce. To make generic medicines and fertilizer related services easily available to farmers at the rural level, Primary Agriculture Societies have been enabled to run Pradhan Mantri Jan Aushadhi Kendras and Kisan Samriddhi Kendras, due to which 36193 such Primary Agriculture Credit Societies have become functional today. In addition, the Ministry of Co-operation has set a target of increasing milk production of dairy cooperatives by 50% in the next five years under Shwet Kranti 2.0. To strengthen the sugar cooperative mills of the country, a loan scheme of Rs. 10000 crore has been launched and their old hard claims have been resolved, due to which

such mills have received relief of more than Rs. 46000 crore. While the esteemed Prime Minister of the country is moving forward with the resolution of Developed India-2047 and the esteemed Home and Cooperation Minister is moving forward with the approach of Cooperatives through which the first university in the cooperative sector of India is being established through this Act. The Government has so far worked for the sugar mills and agriculture sector. NCDC has worked for the development of the cooperative sector. But so far no specific policy or process was decided for training, education, research, rural development, improvement in the efficiency of institutions in cooperatives. By bringing all under this one "umbrella", the scope of cooperative activities will increase and it will be possible to survive in global competition. A proposal has been submitted to establish "Tribhuvan Co-operative University" with the aim of giving a holistic educational form to the cooperative movement in the country. The establishment of this university will prepare a new educated generation and professionals for the sound administration and all-round development of cooperative organizations, changes will be made according to global standards, the efficiency of the organizations will increase and the country's organizations will be developed by making the cooperative movement compatible with global competition. The National Cooperative Development Corporation is running the "Youth Cooperative Cooperative Enterprise Support and Innovation Scheme" across the country, its main objective is to promote newly formed cooperative societies and provide assistance to societies that have been functioning for three months. Under this scheme, co-operative societies from the North-Eastern states, co-operative societies selected by NITI Aayog and societies in which 100% members are SC, ST, Divyang and women members get assistance on the basis of 80:20. The National Cooperative Development Corporation has also launched the following other schemes with the aim of strengthening farmer cooperatives and increasing crop production. The 'Ayushman Sahakari' scheme covering hospitals, health care, medical nursing and paramedical education and health insurance is in operation. Many such schemes are being run by the Ministry of Co-operation. This Bill is oriented to give momentum to the activities in the co-operative sector in the coming days. I welcome this Bill.

4.00 P.M.

**उपसभाध्यक्ष (श्रीमती धर्मशीला गुप्ता):** माननीय सदस्य, Shri Narhari Amin, आपका समय समाप्त हुआ। माननीय सदस्या, सुश्री दोला सेन। आपका समय पाँच मिनट है।

MS. DOLA SEN (West Bengal): Thank you, Vice-Chairman, Madam, for giving me an opportunity to speak. Thanks to our party, All India Trinamool Congress, and our leader, hon. Mamata Banerjee, for giving me the opportunity to speak on the "Tribhuvan" Sahkari University Bill, 2025.

Sir, the All India Trinamool Congress demands that this Bill should be sent to a Committee. Don't rush this like you rush through other Bills. [&] "We want that this Bill be sent to a Committee." Madam, this Bill talks of cooperatives. However, the Government's true intention on cooperatives is very different. In 2023-24, the Union Government utilized only three out of five rupees it allocated for cooperatives in the Budget. [&] "Only 3 rupees out of 5 rupees, Madam"! The biggest fund slash by the Ministry was on computerization of Primary Agricultural Credit Societies and grants to States. I want to ask in this House: Why is this Government so anti-farmer? Why are you so anti-federal? After all, cooperatives are a State subject. Only Multi-State Cooperatives are under the Union List. Then, why are you cutting the grants to States? And, then you talk about cooperative federalism! [&]"Why so much opposition to the farmers? Why so much opposition to federalism? Why so much opposition to the opposition-ruled State Governments? Cooperative societies, according to the Constitution, is enumerated in the State List." Madam, another example of their anti-federal mindset is the funds disbursed by the National Cooperative Development Corporation in 2024. Only Rs. 3 crores was given to my State, West Bengal, that has 9th highest development corporation, in 2024, whereas Rs.2,800 crores was given to a State that has 18th highest cooperative societies! The difference between these two States is simple. One is BJP-ruled and another is ruled by a leader who understands cooperating way better than the Treasury Benches. [&]"In states, where there is a double engine Government, a sum of Rs. 2800 crore has been allocated, whereas, our opposition-ruled State has been granted a paltry sum of Rs. 3 crore."

On the one hand, the Government claims that micro-ATMs are being set up within cooperative societies to provide easier access to banking services. However, on the other hand, the RBI has increased charges on withdrawal of money from rupees 2 to rupees 23 per transaction. This makes me ask you: Why are you so anti-poor? Why so anti-people? Why are you imposing such heavy penalties on people for withdrawing their own money from ATMs? [&] "Why so much opposition to the poor?

[&] English translation of the original speech delivered in Bengali.

Now one would require to pay a charge of 23 rupees for withdrawing one's own money from ATM, Madam?"

Can you have a look at the Home and Cooperation Minister's reply in this discussion on the Bill in the Lok Sabha, where he claimed that this university would train individuals annually and lead to job creation in the cooperative sector? Let me give some statistics on the track record of this Government. Under their flagship programme, PMKVY, only 15 per cent of the trained candidates were placed under the programme. In fact, the placements have been dwindling since PMKVY 4.0. Half of the college students are not ready to be employed after graduating, and only 4 out of 10 youth in the workforce possess formal skills.

Eighty per cent of the unemployed are youth, and 1 in 3 youth are neither in education or employment, nor in training; women make up 95 per cent of this group. This is their track record. Whereas, when I compare this to my home State Bengal, I am proud to say that today in Bengal; we have over 30,000 cooperatives, employing nearly 90 lakh people. In fact, if we look at women in Self-Help Groups, Bengal has the second-highest number of women mobilised in Self-Help Groups, with over 1 crore women; whereas, hon. Prime Minister and hon. Home Minister's home State, Gujarat, has only around 28 lakh women in Self-Help Groups. [&] "If you look at West Bengal, approximately 90 lakh people work in 30,000 cooperative societies across the State and in terms of Women's' Self-help Groups, Bengal is at 2nd position in the country, where about one crore women are employed. Whereas, in Gujarat, only 28 lakh women are employed".

Learn from our three-time outstanding Chief Minister. She is one of the most respected leaders across the world, who recently addressed Oxford University, showcasing the success story of Bengal, that is, Bengal's development. She is unparalleled and unlike mainstream politics in all respects. I leave you three suggestions. One, send this Bill to the Department-Related Standing Committee on Education for more scrutiny. *

**उपसभाध्यक्ष (श्रीमती धर्मशीला गुप्ता):** माननीय सदस्य, कृपया आप बैठ जाएं। ...(**व्यवधान**)... माननीय सदस्य, आप शांत रहें, बैठ जाएं। ...(**व्यवधान**)...

MS. DOLA SEN: *

[&] English translation of the original speech delivered in Bengali.

**उपसभाध्यक्ष (श्रीमती धर्मशीला गुप्ता)**: माननीय सदस्य, आप बिल पर ही बोलें। यह रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है, आप बिल पर ही बोलें। माननीय सदस्य, आपका बोलने का समय समाप्त हुआ। ...**(व्यवधान)**...

MS. DOLA SEN: * इस बिल को कमिटी में भेजिए, thank you.

**उपसभाध्यक्ष (श्रीमती धर्मशीला गुप्ता)**: धन्यवाद। श्री के.आर.एन. राजेश कुमार। आपके बोलने का समय 9 मिनट है।

SHRI K.R.N. RAJESH KUMAR (Tamil Nadu); & Madam Vice Chairman, I thank you very much for giving me the opportunity to speak on 'The "Tribhuvan" Sahkari University Bill, 2025'. I thank hon. Chief Minister of Tamil Nadu, *Thalapathy* M.K. Stalin, hon. Deputy Chief Minister of Tamil Nadu, Brother Udhayanidhi and also our party leader in this House, Brother Tiruchi Siva, for giving me this opportunity. It was in Thiruvuru village of Tamil Nadu, the co-operative society was first formed in India in the year 1904. It is our State, Tamil Nadu, which first introduced co-operative system in the country. I would like to register this fact in this House as my duty. The objective of this Bill is to establish a Co-operative University. There are various Ministries and various Departments under the Union Government. Can each and every Ministry establish a University? Usually they have to be established under the Central University Act. Only if they are established under the Central University Act, University Grants Commission gives its approval to the Degrees offered by the Universities.

Two years ago, in the same House, a Bill was passed to establish a University which would function under the Ministry of Railways. It was established under the Central University Act. This was the convention for many years. But this University is not established under the Central University Act. It is autonomously set up under the Ministry of Cooperation through this Bill. Whether this University has the approval of the UGC, whether the post Graduate courses and the research degrees awarded by this University has the approval of UGC, is to be clarified. I would like to know these facts.

Madam, this University is named as 'The "Tribhuvan" Sahakari University'. It is going to be established in the State of Gujarat. We welcome that it is named after a great leader of Gujarat. How can we understand the term 'Sahakari'? It means co-operatives. How can people from non-Hindi background understand the term

---

* Not recorded.

& English translation of the original speech delivered in Tamil.

'Sahakari'. We are following two language formula in Tamil Nadu. Many States are following two language formula. In this House, a former Prime Minister had approved the usage of two language formula in many States. This principle had been followed at many instances during the rule of Congress party also.

If this University is established in the name 'The "Tribhuvan" Sahakari University', will the same name continue in future also? It may continue as The "Tribhuvan" Sahakari University' even if it is written in English. I would like to recommend renaming of this University as 'Co-operative University' in this Amendment itself. Only then, will the real objective come into existence. People from non-Hindi background also will understand the significance of this University.

Hon. Vice Chairman Madam, not only in Tamil Nadu, but also in various States of India, many universities offer Graduate and Post Graduate courses with respect to co-operative sector. There is an institute by name National Council for Cooperatives Training which functions under the Union Government. Twenty-one colleges are affiliated to this Council. Vaikunth Mehta National Institute of Cooperatives, Pune is also functioning under the Council. It is a very popular institute at the international level. Many Such institutes also cater to the needs of co-operative education. Then, what is the necessity of setting up this Unverisity? Our former Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru laid the foundation for setting up of many universities. It is our duty not to spoil that structure.

The objective of setting up this University is not clear. Co-operative trainings are given by the respective State Governments in many states. Then, what is the need for establishing this University? Madam, now you are offering a course in co-operative sector. What would be the employment opportunities for those, graduated from this University? It is a great question mark. Nowadays, modernisation is spreading at a rapid pace. Computerisation is entering almost all fields. If students complete graduation from this University, what is the guarantee for their employment. It has to be explained.

Madam, in this Bill, many new terms are used. It is mentioned as an Institute of National Importance. It has been mentioned as a Centre of Excellence. We agree with these objectives. But what is the source of fund for this Institute? It is nowhere mentioned in this Bill about the source of funds needed for this Institute. I would like to point out this issue here.

Madam, many co-operative societies are functioning under various ministries. Significantly, there are various co-operatives functioning under various Ministries. The Ministry of Cooperation should formulate co-operative policy, should allocate funds

for the schemes meant for cooperatives, and should also have future plans for the development of co-operatives. It is my duty to record this view in this House. But now, the Ministry aims to take control of all the co-operative societies under its administration.

I would like to mention about IFFCO, Indian Farmers Fertiliser Co-operative Limited. It is a well-established co-operative society. It has been functioning efficiently since independence. It was under the Ministry of Chemicals and Fertilisers. But now, it has been brought under the administrative control of the Ministry of Cooperation. It is good for any institution to function under the respective Ministry. But now, the Institute which was functioning under the Ministry of Chemicals and Fertilisers is brought under the control of the Ministry of Cooperation. What is the objective behind this transfer of administrative control? A co-operative society functioning for a particular sector should be under the administrative control of that particular ministry. Only then can the challenges be faced. For example, during the Ukraine war, the role of IFFCO was significant.

**उपसभाध्यक्ष (श्रीमती धर्मशीला गुप्ता)**: माननीय सदस्य, आपका समय समाप्त हो गया है, Please conclude.

SHRI K.R.N. RAJESH KUMAR: One minute, Madam. [&] What is the difference that is going to happen due to this change? What benefit are we going to get? What are the advantages due to this change of Ministries? IFFCO played a vital role in efficient functioning of the Ministry of Fertilisers. Moreover, in this Bill, the University was not established newly. Already an institute for Dairy and Animal Husbandry, was functioning in Anand, Gujarat. That institute has been upgraded to the status of a University by this Bill. An Institute has been renamed and re-registered as a University. Is it acceptable?

Madam, nowadays, the Ministry of Cooperation is announcing a scheme, 'One District, One Co-operative Bank'. Now, the scheme is only at the naming stage. But more fund has to allocated for this 'One District, one Co-operative Bank' scheme. More funds have to be allocated to NABARD also if this Ministry is functioning for the welfare for co-operative societies. With these words, I conclude my speech. Thank you for giving me this opportunity."

---

[&] English translation of the original speech delivered in Tamil.

**उपसभाध्यक्ष (श्रीमती धर्मशीला गुप्ता)**: माननीय सदस्य, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। डा. अशोक कुमार मित्तल, आपके पास सात मिनट हैं।

**डा. अशोक कुमार मित्तल** (पंजाब): उपसभाध्यक्ष महोदया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आज आपने मुझे 'त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी बिल, 2025' पर बोलने का अवसर दिया है। महोदया, यह एक अच्छी पहल है और कोऑपरेटिव क्षेत्र को शिक्षा से जोड़ने का एक अच्छा प्रयास भी है। कोऑपरेटिव की धारा बिल्कुल शांत नदी की तरह बहती है, यह किसी की सीमा नहीं देखती, किसी मंजिल को नहीं देखती, यह जब भी जाती है, विकास के छोटे-बड़े बीज बोती हुई जाती है, आगे चलती जाती है और आर्थिक सहयोग को विकसित करती है। भारत में सहकारिता की परंपरा काफी पुरानी है। अगर हम इतिहास की ओर देखें, तो महात्मा गाँधी जी ने ग्राम स्वराज के विचार के माध्यम से, खादी और ग्रामीण उद्योगों के माध्यम से सहकारिता को बढ़ावा दिया और इसको आज़ादी की लड़ाई से भी जोड़ा, मतलब यह है कि यह हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है! महोदया, श्री त्रिभुवन भाई पटेल जी जैसे अन्य किसानों ने इसे आगे लाकर इस विचार को साकार किया और इस सहकारिता से जन्मी 'अमूल' भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी ब्रांड बन चुका है। मैं आज इस मौके पर वर्गिस कुरियन जी को भी नमन करता हूं कि उन्होंने भारत में कोऑपरेटिव मूवमेंट को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान दिया।

महोदया, यह विधेयक उस समय आ रहा है, जब युनाइटेड नेशन्स ने 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव घोषित किया हुआ है। हम जानते हैं कि आज भारत में 8 लाख से अधिक सहकारी समितियां हैं, जिनमें 30 करोड़ सदस्य जुड़े हुए हैं। इसका मतलब यह है कि हमारी सोसाइटी का एक बहुत बड़ा सेगमेंट इस सेगमेंट से जुड़ा हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि यह बिल कोऑपरेटिव क्षेत्र के लिए वही कार्य करेगा, जो IITs ने इंजीनियरिंग के लिए और IIMs ने मैनेजमेंट एजुकेशन के लिए किया है। यह तभी संभव हो पाएगा, जब यह एक डायनेमिक यूनिवर्सिटी बने, एक मल्टी-डाइमेंशनल यूनिवर्सिटी बने और एक इंटर-डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी बने।

अब मैं कुछ बातें बिल के प्रावधानों पर करना चाहूंगा। क्लॉज 4 के तहत इंस्टिट्यूशन ऑफ रूरल मैनेजमेंट आणंद को एक विश्वविद्यालय के रूप में विकसित करने का प्रावधान है और इसका नाम त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय है। सरकार ने इसके लिए 500 करोड़ का फंड भी घोषित किया है। यह विश्वविद्यालय एक Institute of National Importance के रूप में घोषित किया जाएगा, जो कि एक अच्छा कदम है। इसके साथ-साथ आईआरएमए, जो पुराना इंस्टिट्यूट चल रहा है, उसको भी सेंटर ऑफ एक्सिलेंस घोषित किया जाएगा और उसकी ऑटोनमी को मेन्टेन रखा जाएगा। क्लॉज 6 में विश्वविद्यालय के उद्देश्य स्पष्ट किए गए हैं, जैसे कि कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए ट्रेन्ड मैनपावर तैयार करना, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के कर्मचारियों और बोर्ड मेम्बर्स को ट्रेनिंग देना, रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ावा देना और इस क्षेत्र में StartUps, innovation और entrepreneurship के लिए भी जरूरी कदम उठाना।

अब मैं आगे बढ़ते हुए कुछ सुझाव देना चाहूंगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी में पीढ़ियों से कुछ लोगों ने बहुत ज्यादा योगदान दिया है और वे इस मूवमेंट से भी जुड़े रहे हैं, जैसे शुगर मिल्स हैं,

डेयरी यूनियन्स हैं, एपीएमसीज़ हैं, वुमेन सोसाइटी हैं, किसान ऑर्गेनाइजेशन्स हैं। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि ऐसे लोग, जो इसमें पीढ़ियों से जुड़े हुए हैं, उनको एडमिशन में प्राथमिकता दी जाए और उनको नौकरियों में भी प्राथमिकता दी जाए, यानी उनके लिए इस बिल के अंदर ही विशेष रिज़र्वेशन का प्रावधान किया जाए। इस विधेयक के क्लॉज़ 7 में एक प्रावधान है कि विश्वविद्यालय अपनी जरूरत और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए outlying campus या स्किल डेवलपमेंट कैम्पस खोल सकता है। आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से इस अवसर पर एक मांग करूंगा। मैं पंजाब से आता हूं और पंजाब एक ऐसा राज्य है, जिसने कोऑपरेटिव मूवमेंट में सबसे ज्यादा सहयोग दिया है। जब देश की खाद्य सुरक्षा की बात आई, तब पंजाब सबसे आगे आकर खड़ा हुआ। यदि देश में ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सेसफुल हुआ, तो उसमें भी सबसे ज्यादा योगदान पंजाब का रहा और पंजाब ने पूरे देश का पेट भरा। पंजाब में वेरका, सोहना और पंजाब एग्रो जैसी सरकारी संस्थाएं भी हैं, जिनका इसमें महत्वपूर्ण योगदान है।

मैं सरकार से फिर दोबारा मांग करूंगा कि त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी का जो सबसे पहले outlying campus खोला जाए, वह पंजाब में खोला जाए। यह माननीय मंत्री जी से मेरा निवेदन है और मुझे लगता है कि इसमें बाकी लोग भी मुझे सपोर्ट करेंगे। सहकारिता के बारे में कई बार हमें लगता है कि वह सिर्फ आर्थिक संरचना है, बल्कि वह एक आर्ट भी हो सकती है और वह एक साइंस भी हो सकती है, क्योंकि इसमें हर क्षेत्र आ जाता है। इसमें डेयरी भी आती है, कृषि भी आती है, टेक्सटाइल का रॉ मैटेरियल भी आता है, बैंकिंग भी कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक अभिन्न अंग है, हाउसिंग भी उसमें आता है, फिशरीज़ भी आता है, हैंडीक्राफ्ट भी आता है और कॉटेज इंडस्ट्रीज भी आता है। इसमें बहुत अलग-अलग मुद्दे आते हैं। ...(**व्यवधान**)... मेरा सुझाव होगा कि इस विश्वविद्यालय में सेक्टर-स्पेसिफिक कोर्सेज शुरू किए जाएं, जिससे कोऑपरेटिव सेक्टर की सप्लाई चेन के हर अंग को मजबूती मिले और ग्राउंड लेवल से ग्लोबल लेवल तक भारत की सहकारिता को मजबूत बनाया जा सके। यह आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मेरा निवेदन रहेगा। क्लॉज 9 में सरकार के पास कुछ एक्सेसिव पावर्स हैं, यहां तक कि वह यूनिवर्सिटी के किसी डिसीजन को भी रद्द कर सकती है। एक तरफ हम इसे Institute of National Importance बना रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कह रहे हैं कि सरकार बीच में कभी भी उसके किसी फैसले को रद्द कर सकती है, तो यह थोड़ा contradictory है। इसलिए मैं आपके through मंत्री जी से निवेदन करूँगा कि उसकी importance को बचाए रखने के लिए, उसके eminence के status को बचाए रखने के लिए सरकार की दखलअंदाजी न हो और सरकार को उसके किसी फैसले को रद्द करने का अधिकार न हो।

मैडम, मैं एमपीज़ की तरफ से मंत्री जी से एक निवेदन करूँगा कि बहुत से केंद्रीय विश्वविद्यालय में Member of Parliament को Governing Body में एक सीट दी जाती है, लेकिन इसमें वह प्रावधान नहीं है। हममें से बहुत से Members of Parliament ऐसे होंगे, जो cooperative movement से जुड़े हुए हैं, जो किसान movement से जुड़े हुए हैं। ...(**समय की घंटी**)...

**उपसभाध्यक्ष (श्रीमती धर्मशीला गुप्ता)**: माननीय सदस्य, please conclude.

**डा. अशोक कुमार मित्तल**: मैडम, मुझे बस आधा मिनट दे दीजिए। यह हम सभी की माँग है। इसलिए उसमें एमपीज़ में से एक मेम्बर जरूर बनाया जाए, ताकि वे हमारे एमपीज़ का फायदा उठा सकें। ...(**समय की घंटी**)...

**उपसभाध्यक्ष (श्रीमती धर्मशीला गुप्ता)**: धन्यवाद, माननीय सदस्य।

**डा. अशोक कुमार मित्तल** मैडम, बस आखिरी लाइन रह गई। चूँकि यह मंत्रालय अमित शाह जी के पास है, तो हम सबकी उम्मीद बढ़ जाती है कि इसमें बहुत बढ़िया काम होगा। इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ ...

THE VICE-CHAIRPERSON (SHRIMATI DHARMSHILA GUPTA): Please conclude.

**डा. अशोक कुमार मित्तल**: मैडम, मैं बस conclude कर रहा हूँ। इसमें मेरे suggestion के ऊपर ध्यान दिया जाए। मैडम, मैं बस दो लाइनें कह कर अपनी बात खत्म करूँगा। अब ज्ञान से सहकार का दीप जलाएँ हम।

**उपसभाध्यक्ष (श्रीमती धर्मशीला गुप्ता)**: माननीय सदस्य, आपका समय समाप्त हो गया। आपकी बात आ गई, प्लीज़ बैठ जाइए। श्री शुभाशीष खुंटिया जी। आपके पास 8 मिनट्स हैं।

SHRI SUBHASISH KHUNTIA (Odisha): Hon. Vice-Chairman, Madam, today, on Utkal Diwas, we honour Odisha's rich cultural heritage and contributions. I extend my best wishes to all. *Bande Utkal Janani.*

Madam, thank you for giving me this opportunity to speak on the Tribhuvan Sahkari University Bill, 2025. मैडम, यह बिल हमारी अर्थव्यवस्था के दो महत्वपूर्ण स्तंभों, शिक्षा और cooperative से जुड़ा हुआ है। At first glance, this Bill appears to be about strengthening co-operative education. लेकिन असल में यह cooperative संस्थानों को शिक्षा के नाम पर केन्द्र के नियंत्रण में लाने का प्रयास है। मैडम, हमारे संविधान की Concurrent List में शिक्षा का विषय आता है, जिसका मतलब है कि केन्द्र और राज्य, दोनों को मिल कर फैसला लेना चाहिए, लेकिन यह सरकार राज्य से बिना सलाह किए दिल्ली से सीधे फैसले थोपने की आदत बना चुकी है।

I would like to mention some of the Clauses of the given Bill which promote centralisation. Clause 2 declares this newly-established University as an Institution of National Importance ensuring Central control. Clauses 11 and 15 bring IRMA under this new University by establishing the Institute of Rural Management and School within this. Clause 9 gives the Central Government power to review and issue directions threatening control. Is this co-operative federalism? Where is the dialogue

with the States in taking decisions mentioned in this Bill? Where is the discussion with existing co-operative institutions in taking decisions mentioned in this Bill? This is a complete violation of the constitutional provision given under Schedule VII of the Constitution. सरकार cooperative federalism की बात करती है, लेकिन हकीकत में यह cooperative hijacking कर रही है।

मैडम, हर राज्य का सहकारी मॉडल अलग होता है। The co-operatives function according to local needs and regulations and their operations vary from State to State. These involve local techniques, technicians and different styles of working. For example, the sugarcane co-operatives of Maharashtra and Uttar Pradesh are different from the dairy co-operatives of Gujarat. In Odisha, we have palm cultivation co-operatives, fishery co-operatives and Mission Shakti Women-led SHGs, each with distinct structures. सब अलग-अलग ढंग से काम करते हैं। Yet, this Bill fails to recognise this variation and forces all co-operatives to work under one Central framework, undermining the very essence of the decentralisation.

The IRMA was established with State participation and operates independently, but this Bill takes the opposite approach of full Central control. Why? This is not co-operative education. This is co-operative capturing. मैडम, अगर सरकार वास्तव में cooperatives को मजबूत करना चाहती है, तो उसे जनता को अधिकार देना चाहिए। Odisha has already empowered 70 lakh women through Mission Shakti under the leadership of our beloved leader, Shri Naveen Patnaik, by giving them direct control over the Self-Help Groups. Why is this Government afraid of empowering the people?

सरकार महिलाओं के empowerment के लिए ओडिशा में university क्यों स्थापित नहीं कर सकती, जबकि इसके लिए पहले से ही एक मजबूत structure मौजूद है? इसे बस थोड़ा बढ़ावा देने की जरूरत है, जिससे बड़े और प्रभावी परिणाम मिल सकते हैं। मैडम, सरकार इस विश्वविद्यालय का नाम त्रिभुवन दास पटेल जी के नाम पर रख रही है। He was the pioneer of India's cooperative movement. त्रिभुवन जी महात्मा गांधी जी के follower थे। वे decentralization, सहकारिता, सशक्तिकरण और स्थानीय उद्योगों के पक्षधर थे, जबकि यह बिल विपरीत दिशा में जाकर, सहकारी संस्थाओं का कंट्रोल दिल्ली को दे रहा है।

Madam, it is good that the Government has proposed to set up this university. In this context, I would like to say that Odisha is home to some of the largest and most-vibrant cooperative movements in the country. Like Mission Shakti, Odisha's Jagannath Temple in Puri runs one of world's largest cooperative kitchens serving lakhs of devotees daily. Traditional artisans, carpenters, painters and cooks play a crucial role in Odisha's economy through cooperative framework. Why not establish a Skill Development University in Odisha to strengthen Mission Shakti, food processing cooperatives and rural artisans and empower women and people at large in a proper

cooperative framework, and why not set a Food Craft Institute in Puri? सरकार यदि co-operative education को मजबूत करना चाहती है, तो ओडिशा को प्राथमिकता देनी चाहिए।

मैडम, ओडिशा में 40 परसेंट एससी-एसटी आबादी है, भारत के कुल खनिज उत्पादन में ओडिशा का योगदान 50 परसेंट है, लेकिन लाभ किसे मिलता है - not the tribal people who live on this land and who are the true owners of these resources but a handful of corporate players! क्यों? जमीन उनकी, खनिज उनका और उसका फायदा किसी और को! The biggest reason for this exploitation is rise of mine developers and operators as well as firms that act as middlemen reducing tribal people to daily-wage labourers on their own land. क्यों हमारे आदिवासी भाई-बहन अपनी ही जमीन पर एक मजदूर की तरह काम करें और corporates अरबों रुपये का मुनाफा कमाए? हमें MDOs के स्थान पर co-operative mining करनी चाहिए। We need tribal-led mining so that they extract their own minerals and reap the benefits. The Government should establish a Skill Development University for Tribal Cooperative Mining. Madam, cooperatives are not built through bureaucratic control. They grow by empowering people but sadly, the word 'empowerment' is not there in this Government's dictionary. मैडम, भारत में लगभग 8 लाख co-operatives हैं, जिनके 30 करोड़ से अधिक सदस्य हैं और हर पांचवां भारतीय किसी न किसी सहकारी संस्था का हिस्सा है। 75 वर्ष में भारत को पहली बार एक सहकारी विश्वविद्यालय मिलने जा रहा है।

Madam, this is a historical moment. If this Bill is to serve its true purpose, it must do the following - ensure academic and financial autonomy for the university, respect the role of States in cooperative education, support decentralized cooperative education models, encourage participatory governance not bureaucratic interference. It should take help from the local regional college, which will bring expertise from all sectors including technical, health, agricultural, rural management and many more. मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस विधेयक में जरूरी संशोधन करे, ताकि यह वास्तव में co-operatives को मजबूत कर सके।

मैं अंत में यही कहना चाहता हूं कि, नींव के बिना इमारत नहीं टिकती है और बिना जनभागीदारी के विकास दिखता नहीं है। यह बिल अगर रोशनी है, तो प्रकाश हर जगह पहुंचना चाहिए, न कि सिर्फ दिल्ली के दरबार में झलकना चाहिए। धन्यवाद, वंदे उत्कल जननी! जय जगन्नाथ! मैं एक बार फिर आप सभी को 'उत्कल दिवस' की बधाई देता हूं, जय जगन्नाथ!

**उपसभाध्यक्ष (श्रीमती धर्मशीला गुप्ता)**: माननीय श्री अयोध्या रामी रेड्डी आला। आपके पास 8 मिनट का समय है।

SHRI AYODHYA RAMI REDDY ALLA (Andhra Pradesh): Thank you, Madam, for giving me the opportunity to speak on the Tribhuvan Sahakari University Bill, 2025.

The purpose of this Bill is to establish IRMA as a Tribhuvan Sahakari University. The objectives are very clear. It is going to bring education, training and capacity building in cooperative sector. It also undertakes R&D activities in related areas. Through the University, this Bill is also going to offer the postgraduate degrees, distance learning programmes, e-learning programmes and courses on centre of excellence in cooperative sector, which is very welcoming. It is also going to establish outlying campuses or affiliate institutions across India and abroad. This is also a very good objective. The current IRMA will become an autonomous school within the University. It will become centre of excellence for rural management for the entire country, which is, again, very welcoming. Through this Bill, the University is going to be instituted for systematic study of cooperative institutions. It is a laudable achievement and benefits the non-credit sectors such as weavers, artisans, marketing professionals and others. Our country has used this economic model as a vehicle, as a symbol of democratic wealth creation. Identifying the potential, our Prime Minister aptly called it a middle path between socialism and capitalism where wealth is created in a democratic manner with collective ownership.

Madam, there are some issues around the cooperative sector. One of the most important issues is non-fulfillment of announced cooperation, that is, linked targets. I want the Union Minister of Cooperation to look at how cooperative societies played a huge role in the country. It is accounting for 19 per cent in agriculture credit, 35 per cent in fertilizer distribution, 25 per cent in fertilizer production, 31 per cent in sugar production, 10 per cent in production and procurement of milk, 13 per cent in wheat procurement, 20 per cent in paddy procurement and 21 per cent in fish production. In this area, the linked targets to the sector are not properly fulfilled. I want the Ministry to look into it. Also, there is stagnant allocation of National Cooperative Development Corporation Fund, the NCDC Fund. If you look at it, the allocation of NCDC has been stuck at Rs. 500 crore for the past two years. This is a failure on the promise that would have otherwise gone into strengthening and adding fuel to the growing cooperative sector in the country. Also, there is sectoral disparity within cooperative societies. The National Cooperative Plan included reducing regional disparities in the cooperative sector. However, attention must also be paid to reducing disparities in between the sectors. The 2023-24 cooperative societies data shows that the handloom sector, agro-processing and women's welfare in lower ranks of both society and sector count within cooperative institutions. This is yet another gap that remains unresolved. As we stand to discuss this Bill, I want that the sectoral disparity must be addressed. We also need to look at the plight of the

handloom cooperatives in Andhra Pradesh. Actually, Andhra Pradesh's handloom sector is facing a severe crisis today. The per capita income is very low, as low as 57 rupees per day, which is even less than the NREGA payments. The Andhra Pradesh State Handloom Weavers Cooperative Society also appoints a huge number of people. More than two lakh people are its members. There is a lot of struggle that is going on for raw materials, quality of the material and getting the right prices for that.

Even to meet the operating expenditures, there is a serious problem. Also on formal banking credit, working capital aid and some welfare basic things like ESI and EPF benefits. There is a huge problem that this Andhra cooperative sector is facing. Hence, I request the Minister of Cooperation to remove the GST on handlooms; allocate Rs.3,000 crore for the protection of handloom sector in Andhra Pradesh; issue immediate orders to support the weaver community by implementing a scheme of free 200 electricity units, clearing pending yarn subsidies and interest arrears; and establish a handloom welfare fund board for Andhra Pradesh.

Madam, since we are talking about the University Bill, I want to tell you that there were some 17 Vice-Chancellors in Andhra Pradesh who were directly or indirectly forced to resign in one go. This is what I actually wanted to say. It is in the Concurrent List where State and Centre work together. In our federal system, this has never been experienced in this form. It should be certainly looked into by the Central Government.

Next is dilution of the Nadu-Nedu Scheme and politicisation of educational reforms. In the previous YSR Government, more than 56,000 Government Schools were brought under NADU-NEDU scheme -- more than 15,000 crore in Phase 1 and more than 7,000 crore in Phase 2. A lot of money was spent on it. But that scheme is not properly going on now. There should not be any partiality when it comes to education. The good things that have come should be continued.

Next is, removal of English as a medium of instruction in Andhra Pradesh schools. Former Chief Minister Jagan Mohan Reddy brought in a very good improvement in bringing educational standards for the children in Andhra Pradesh by bringing in English as a medium of instruction. That will help children in accessing global platforms and developing a very strong leadership. They will become CEOs of great institutions in times to come.

Madam, this is a very good Bill. We support this Bill. The Government of India should focus on strategising and structuring key deliverables for implementation. The Government should come out with good models State-wise and sector-wise which

can sustain in times to come. With this, from YSR Congress Party, we support this Bill. Thank you, Madam.

**उपसभाध्यक्ष (श्रीमती धर्मशीला गुप्ता)**: धन्यवाद, महोदय। माननीय सदस्य, श्री संजय यादव, आपके पास पाँच मिनट हैं।

**श्री संजय यादव** (बिहार): मैडम, छः मिनट होंगे।

**उपसभाध्यक्ष (श्रीमती धर्मशीला गुप्ता)**: पाँच मिनट हैं।

**श्री संजय यादव**: मैडम, मुझे "त्रिभुवन" सहकारी यूनिवर्सिटी विधेयक, 2025 की चर्चा में भाग लेने हेतु समय देने के लिए आपका धन्यवाद। मैडम, यह बिल IRMA की academic freedom और institutional autonomy को completely undermine करता है। जब मैं इस बिल की Governing Body की composition को देख रहा था, तो पता चला कि इसमें State representation को बिल्कुल minimize कर दिया गया है। इसमें केवल चार Principal Secretaries को include किया गया है, वह भी rotation basis पर। सबसे दुखद बात यह है कि जब आप Governing Body का social composition या composition देख रहे हैं, तो पता चलता है कि उसमें वंचित, उपेक्षित, SC, ST, OBC के लिए इन्होंने कोई सीट रिजर्व नहीं की है। SC, ST, OBC को Governing Body से completely boycott कर दिया गया है। यह दर्शाता है कि इस सरकार में प्रायः जितने भी Bills आ रहे हैं, अगर हम उन्हें देखते हैं, तो उनमें SC, ST, OBC को हर स्तर पर eliminate करने का एक कुचक्र रचा जा रहा है। इसकी Governing Body में representation को लेकर मेरा यह सुझाव है कि इसमें 20 परसेंट PACS के representatives होने चाहिए और 50 परसेंट स्टेट के representatives होने चाहिए।

मैडम, जब इस विधेयक में हम reservation policy देखेंगे, तब इसमें पाएंगे कि faculty recruitment में academic council हो, administrative role हो या students के admission हों, उनमें SC/ST और OBC के लिए reservation policy कैसे लागू होगी, इसके लिए कोई स्पष्टता नहीं है। जब आप एक यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, तो उसमें आप फैकल्टीज रिक्रूट करेंगे, बच्चों का एडमिशन होगा, तो आप बहुजनों को कैसे छांट सकते हैं? अब प्रायः देखने में आता है कि जितने भी रिक्रूटमेंट हो रहे हैं, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो - हम सहकारी यूनिवर्सिटी की ही बात नहीं कर रहे - उसमें पिछड़े, अति पिछड़े, दलित और आदिवासियों को छांटने के लिए इनकी पहली चाल यह होती है कि एकल पद को सृजित किया जाता है। एकल पद में बोल दिया जाता है कि आरक्षण नीति लागू नहीं होगी।

दूसरा, यदि चार-पांच पद हों, जहाँ आरक्षित वर्गों के लोग अप्लाई कर सकें, तो उसमें यह कह दिया जाता है कि NFS - Not Found Suitable, यानी देश की 80 फीसद आबादी, जिसमें पिछड़े, दलित, अति पिछड़े शामिल हैं, उनमें कोई भी कैंडिडेट सूटेबल नहीं मिलता। इस देश के मूल निवासियों में इनको कोई एक कैंडिडेट ऐसा नहीं मिलता, जो उस चीज़ के लिए सूटेबल है।

**उपसभाध्यक्ष (श्रीमती धर्मशीला गुप्ता):** कृपया, आप बिल पर बोलिए।

**श्री संजय यादव:** मैं बिल पर ही बोल रहा हूं। बिल में ही रिज़र्वेशन की कोई स्पष्टता नहीं है। मैं यही बात बोल रहा हूं। यही नहीं, इसके अलावा जब इस बिल में fee capping, तो इन्होंने फीस रिवीज़न को inflation के index से relate कर दिया है। मतलब महंगाई बढ़ेगी, तो उसके अनुपात में फीस भी बढ़ेगी। जो एससी, एसटी या ओबीसी के लोग हैं, वे कहां से इस महंगाई के अनुपात में फीस भरेंगे। उस पर कैपिंग होनी चाहिए। इस बिल के माध्यम से हमारी मांग है कि आपको आरक्षित वर्ग के बच्चों को रियायत देनी चाहिए और फीस को कैप करना चाहिए।

आप सहकार से समृद्धि की बात करते हैं, लेकिन जब तक किसान के सुख, सम्मान और आय में वृद्धि नहीं होगी, तब तक समृद्धि कहाँ से आएगी? मैडम, जैसे दीया और बाती का, अंकुर और माटी का रिश्ता होता है, वैसे ही सहकारिता और कृषि का, तथा सहकार जनों और किसानों का रिश्ता होता है। जब तक आप किसानों को आवश्यक सुविधाएँ नहीं देंगे, उनकी आय में वृद्धि नहीं करेंगे, तब तक सहकार से समृद्धि संभव नहीं।

अब बिहार की बात करें तो वहाँ सहकारिता विभाग क्या कर रहा है? बिहार में सहकारिता विभाग के नाम पर सरकारी खर्चे से कार्यक्रम होते हैं, लेकिन उनमें सिर्फ़ पॉलिटिकल भाषण होते हैं। आप सहकारिता को कैसे बढ़ाएँगे? को-ऑपरेटिव सेक्टर में क्या काम करेंगे? इस पर कोई चर्चा नहीं होती।

बिहार में 8,463 PACS हैं। यदि हम 2014 से अब तक का बजट उठाकर देखें, तो हर साल यह कहा जाता है कि computerization होगा। लेकिन 8,463 PACS में से केवल 226 PACS में ही अब तक हार्डवेयर की आपूर्ति की गई है और उन्हें ऑनलाइन नहीं किया गया है। बिहार में PACS computerization के नाम पर केवल हार्डवेयर डिब्बों में बंद है। न तो कोई ट्रेनिंग दी गई, न कोई ऑनलाइन सिस्टम विकसित किया गया। हार्डवेयर लगाया तक नहीं गया - CPU और मॉनिटर तक नहीं जोड़े गए।

अब यदि हम बिहार में कमर्शियल बैंकों की स्थिति देखें, तो केसीसी (Kisan Credit Card) के तहत कितना लोन दिया गया है? सहकारिता से कैसे समृद्धि होगी? बिहार का क्रेडिट-डिपॉज़िट रेशियो (CDR) देश में सबसे कम है। मतलब, बिहार के किसानों और आम लोगों से पैसा लिया जाता है, लेकिन उन्हें कर्ज़ नहीं दिया जाता। यह कर्ज़ बिहार के बाहर दिया जाता है और फिर उस कर्ज़े को नीरव मोदी, मेहुल चौकसी जैसे लोग लेकर भाग जाते हैं, जबकि बिहार के लोग देखते रह जाते हैं। जो सीडीआर रेश्यो है, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। गतिशक्ति यूनिवर्सिटी भी गुजरात में चली गई, जो सहकारिता इरमा था, वह भी चला गया। मैडम, बिहार में कुछ होना चाहिए। वहां से इतने एमपीज़ हैं, तो वहां भी कोई यूनिवर्सिटी दे दीजिए। गतिशक्ति भी चली गई।

बिहार का जो साख जमा अनुपात है, वह 50 परसेंट है, जो कि राष्ट्रीय औसत से बहुत कम है। बिहार में कृषि ऋण और भी कम मिलता है - केवल 12 परसेंट किसानों को केसीसी लोन मिलता है। पशुपालन और मत्स्य पालन क्षेत्र में तो और भी बुरा हाल है।

यह स्थिति तब है, जब बिहार के लोग NPA नहीं बनाते, यानी वे डिफॉल्ट नहीं करते। फिर भी उन्हें लोन नहीं दिया जाता!

**उपसभाध्यक्ष (श्रीमती धर्मशीला गुप्ता):** माननीय सदस्य, आप सही आंकड़े बताएं। ...(**व्यवधान**)... माननीय सदस्य, कृपया बैठ जाएं।

**श्री संजय यादव**: मैडम, मैं मांग करता हूँ कि बिहार में भी सहकारिता यूनिवर्सिटी या अन्य उच्च स्तरीय यूनिवर्सिटी स्थापित की जाए। ...(**समय की घंटी**)... सब कुछ केवल गुजरात में ही नहीं होना चाहिए।

**उपसभाध्यक्ष (श्रीमती धर्मशीला गुप्ता):** माननीय सदस्य, प्लीज़ कन्क्लूड।

**श्री संजय यादव**: गुजरात को महात्मा गांधी के नाम से जाना जाता है, लेकिन बिहार महात्मा गांधी की कर्मभूमि भी रही है।

**उपसभाध्यक्ष (श्रीमती धर्मशीला गुप्ता) :** माननीय सदस्य, प्लीज़ कन्क्लूड। आपका बोलने का समय समाप्त हुआ।

**श्री संजय यादव**: वहाँ भी सरकार को कुछ ध्यान देना चाहिए, शुक्रिया।

**उपसभाध्यक्ष (श्रीमती धर्मशीला गुप्ता):** माननीय सदस्य, डा. मु. तंबी दुरै। आपके पास बोलने के लिए चार मिनट का समय है।

DR. M. THAMBIDURAI (Tamil Nadu): Madam, I rise to participate in the discussion on the Bill. Madam, this Bill seeks to establish the Institute of Rural Management Anand, Gujarat as "Tribhuvan" Sahkari University, which is now a registered society. The University is going to provide education, training and capacity building in co-operative sector and will undertake research and development activities. The object of the University is that the research and development is more important and not just selling the degrees. What is happening in India is, most of the private universities and deemed universities are only selling degrees and not concentrating on research and development, I want to bring this to your notice.

Now, we are speaking about cooperation. DMK talks about federal cooperation. I want to know: "Is there any cooperation from DMK-ruled Government to the Central Government?" I do not know. If there is no cooperation, how would development take place in Tamil Nadu? There must be cooperation in that. Not only

cooperation from the Government side, there is no cooperation between the Governor of Tamil Nadu and Chief Minister of Tamil Nadu. *...(Interruptions)...* There is no cooperation there also in appointing the Vice-Chancellors. As we are discussing about the University, university means that the Vice-Chancellor would be the head of the university. Without a Vice-Chancellor, how can we run the university? You tell me. In Tamil Nadu, in nine universities, there are no Vice-Chancellors. I was also a Professor teaching in the Anna University. In that Anna University, there is no Vice-Chancellor now. Molestation of a lady took place in Anna University. *...(Interruptions)...* What action was taken? This is very shameful.

Next, I come to the point regarding the UGC guidelines. *...(Interruptions)...* UGC has brought the guidelines on how to appoint the Vice-Chancellors. Now, I have an objection. The present UGC is going to bring in 2025, "without the nomination of the State Government." It is against the federal setup. I am protecting that because I was also an Education Minister. At that time, I had the role to nominate from the Government side — I was one of the selecting committee members — for selecting a Vice-Chancellor. I am telling this because Shri Digvijaya Singh said in his speech that Vice-Chancellors were not appointed in Tamil Nadu, Kerala and said so many other things. Who is responsible for this? The Congress is responsible for this. The UGC regulations, 2010, stipulated that there must be a nominee from the UGC. Who did it? The Congress did it. Who was there at that time? The DMK was the partner of the Government. Therefore, at that time, they accepted this kind of regulation to have a nominee from UGC. Still that regulation is there. Therefore, Governor is asking: "Why is the State Government rejecting to put a UGC nominee?" *...(Interruptions)...* What is their problem? Let them put a UGC nominee and select the Vice-Chancellor. This regulation was brought by UPA Government, DMK and Congress, in 2010. Who is responsible? Therefore, this kind of system is there in Tamil Nadu. How did they conduct the convocation? As there is no Vice Chancellor, convocations are not happening properly. In Madras University, there is no Vice-Chancellor, it is a reputed University. At Anna University, no Vice-Chancellor is there. Like that, there are so many universities. For another one year, I do not think, any appointment would be there in other universities because of the failure of the DMK Government, not cooperating with the Central Government as well as with the Governor to solve this problem. *...(Interruptions)...*

**उपसभाध्यक्ष (श्रीमती धर्मशीला गुप्ता):** माननीय सदस्य, बैठ जाएं। प्लीज़ शांत रहें।

DR. M. THAMBIDURAI: This is the basic problem. *...(Interruptions)...* This is also because Education has come into the Concurrent List. How has it come? Education has come into the Concurrent List because of the Emergency period. Shrimati Indira Gandhi, the Prime Minister at that time, brought Education from the State Subject to the Concurrent List. That is why they are suffering now.

THE VICE-CHAIRPERSON (SHRIMATI DHARMSHILA GUPTA): Please conclude.

DR. M. THAMBIDURAI: They ruled for 18 years. They never bothered to remove these kinds of things. I am once again saying that Tamil Nadu is suffering without Vice-Chancellors in many universities. The State Government should look into this...

THE VICE-CHAIRPERSON (SHRIMATI DHARMSHILA GUPTA): Please conclude. माननीय सदस्य, आपका समय समाप्त हो गया है, कृपया आप बैठ जाइए। Shri Abdul Wahab. आपके पास तीन मिनट हैं

SHRI ABDUL WAHAB (Kerala): Thank you very much, Madam, for giving me three minutes with your courtesy. I proposed about this university last year. I congratulate Amit Shah*ji*. At least, out of these 18 years, I have got one chance of having my proposal accepted. It is very good, everything is good. The only problem is the name and the place. There is a little problem for us. With regard to '*Tribhuvandas*', we do not have anything against him. But the only thing is, it is not George Kurian, but Verghese Kurien. Everybody knows Verghese Kurien. If it was in Kerala and in his name, it would have been wonderful. That is my only regret. In Gujarat, there is only one Anand. But in Kerala, there are many Anands, like ULCC, Kudumbashree and many others. We are not having AIIMS. We are not getting that. Nothing! No national institution is coming. I do not know without the cooperation of Kerala Government and Governor - that also we have accepted now. Pinarayi Vijayan and the new Governor are always sitting together. Okay! But now also, we are not getting. Even this also is in Gujarat. There is nothing wrong with Gujarat. Gujarat is also a part of India. It is not a problem. But why only in Gujarat? That is the only problem. Secondly, last year, I proposed this one and we got it this year. On seeing Mr. Jayant here, I propose for a skill university which should be there. That also should not go to other places or in your place. It should come to Kerala. I have spoken about the name of the university and the location. Another thing that I want to mention is about reservation. I do not know how they are doing it. It is not very clear and, definitely, there will be a Vice-Chancellor. Do not worry, Dr. Thambidurai! It is not a question of

Vice-Chancellor or Chancellor. The only thing needed is cooperation. There is no cooperation between the States and the Central Government. That is what is happening in Kerala. It is for namesake only. The name is the problem. Everything is in the name of 'PM', which our Kerala Government is not accepting. There should be, at least, 'CM'. Instead of 'PM', it should be 'CM', 'Chief Minister *Yojana'*. We are okay with the Hindi word '*Yojana'*. We are not objecting just like Tamil Nadu. We do not worry about any Hindi name. We are only worried about the content. ...*(Interruptions)*... It need not necessarily be in Malayalam. I request the Government that there should be some reservation—I am not asking for Muslims—for differently-abled.

THE VICE-CHAIRPERSON (SHRIMATI DHARMSHILA GUPTA): Please conclude.

SHRI ABDUL WAHAB: Can I get some more time? I can get BJP's time now if I am supporting the Bill. Agreed! See, they are agreeing.

THE VICE-CHAIRPERSON (SHRIMATI DHARMSHILA GUPTA): No, please conclude.

SHRI ABDUL WAHAB: But you are not agreeing. This is the problem. Thank you very much; I am accepting the words of Dr. M. Thambidurai.

THE VICE-CHAIRPERSON (SHRIMATI DHARMSHILA GUPTA): Please conclude. माननीय सदस्य, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। सुश्री इंदु बाला गोस्वामी, आपकेपास दस मिनट हैं, आप अपना भाषण आरंभ कीजिए।

**सुश्री इंदु बाला गोस्वामी** (हिमाचल प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। महोदया, 'त्रिभुवन' सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक, 2025 पर बोलने का अवसर देने केलिए मैं आपकेप्रति आभार प्रकट करती हूं। उपसभाध्यक्ष महोदया, देश केयशस्वी प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में बीते दस वर्ष से अधिक का कार्यकाल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित रहा है। यही कारण है कि यशस्वी प्रधान मंत्री जी ने अपनी दूसरी टर्म में ही सहकारिता क्षेत्र के लिए अलग मंत्रालय की घोषणा की और इस मंत्रालय की जिम्मेदारी भी कुशल संगठनकतारगृह मंतरीजी को दी, जिन्होंने सहकारिता क्षेतरमें एक अगरणी भूमिका निभाई है।

5.00 P.M.

इतना ही नहीं, इस मंत्रालय के लिए 1,186 करोड़ से अधिक के बजट का प्रावधान किया, जो यूपीए सरकार के बजट से लगभग 10 गुना से भी अधिक है। यूपीए सरकार के कार्यकाल 2013-14 में सहकारिता के लिए मात्र 122 करोड़ के बजट का ही प्रावधान था। इतना कम बजट होने के कारण 100 से अधिक सहकारी शुगर मिल्स बंद हो गईं और कितनी ही सहकारी समितियां बजट न मिलने के कारण ठप्प पड़ गईं। मोदी सरकार ने डेयरी सहकारी योजना के अंतर्गत सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों, एफपीओज़ के आधुनिकीकरण और क्षमता निर्माण के लिए 5,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जो यूपीए सरकार से दो गुना ज्यादा है।

उपसभाध्यक्ष महोदया, आज सहकारिता क्षेत्र देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आजाद भारत में पहली बार ऐसा मंत्रालय बनाया गया है, जो ब्रैंड न्यू कॉन्सेप्ट के साथ सहकारिता में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। कोऑपरेटिव सेक्टर का एक separate administrative, legal and policy making framework बनाया गया है, जिसके माध्यम से आज कोऑपरेटिव सेक्टर को सुदृढ़ता देने के लिए, उसके विस्तारीकरण के लिए इस मंत्रालय द्वारा महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और श्री अमित शाह जी के कुशल क्रियान्वयन क्षमता से भारत के सहकारिता सेक्टर में एक नया रेवोल्यूशन आया है। बजट में सहकारिता क्षेत्र को टैक्स संबंधित रियायतें देने से मैनुफैक्चरिंग करने वाली नई सहकारी समितियों को फायदा मिला है।

उपसभाध्यक्ष महोदया, सहकारी क्षेत्र में नए नियम बनाने से और इन्हें आर्थिक सुदृढ़ता देने से अब PACS, डेयरी, मत्स्य पालन, अन्न भंडारण, जन औषधि केंद्र जैसे 30 से अधिक विविध क्षेत्रों में व्यवसायिक गतिविधियां संचालित करने वाली सहकारी समितियां लाभान्वित हुई हैं। मोदी सरकार ने देश में 10,000 एफपीओज़ बनाने का लक्ष्य रखा था। एक अलग सहकारी मंत्रालय होने का नतीजा यह है कि आज देश में 8,000 एफपीओज़ का गठन हो चुका है और इनमें से कई एफपीओज़ की सक्सेस स्टोरीज़ की चर्चा आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो रही है। सहकारी क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी आज 60 प्रतिशत से अधिक हो गई है। मोदी सरकार का मानना है कि सम्पूर्ण सहकार की परिकल्पना महिलाओं की सहकारी आंदोलन में अग्रणी भूमिका के बिना संभव ही नहीं है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार ने अब बहुराज्य सहकारी समितियां, एमएसईज़ और प्राथमिक कृषि साख समितियां, PACS के लिए महिला निदेशकों की नियुक्ति अनिवार्य कर दी है। सरकार का यह कदम महिलाओं को सहकारी समितियों में प्रबंधकीय पदों पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में प्रेरित करेगा। आज डेयरी और कृषि में सहकारिता से जुड़े किसानों में अधिकतर संख्या महिलाओं की है। महिलाओं के सहकारी सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए मोदी सरकार ने सहकार से जुड़ी नीतियों और योजनाओं को प्राथमिकता दी है। मोदी सरकार ने महिलाओं में उद्यमशीलता बढ़ाने के लिए नंदिनी सहकार योजना शुरू की है, जिससे सहकारी समितियों में महिलाओं का नेतृत्व बढ़ा है। एनसीसीटी और वैमनीकॉम जैसी प्रशिक्षण इकाईयों ने डेयरी, हथकरघा, माइक्रो क्रेडिट, ग्रामीण उद्यमिता, मधुमक्खी पालन, औद्योगिक सहकारी समितियों आदि जैसे क्षेत्रों को कवर करते हुए कई कौशल विकास कार्यक्रम आयोजित किए हैं। इनमें महिलाएं मुख्य रूप से प्रतिभागिता के रूप में अपना पार्टिसिपेशन कर रही हैं। वर्ष 2020-21 में लगभग 40,288 लोगों ने प्रशिक्षण लिया, जिनमें लगभग 10,000 महिलाएं थीं, 2021-22 में

लगभग 62,474 लोगों ने प्रशिक्षण लिया, इनमें लगभग 15,000 महिलाएं थीं और 2022-23 में लगभग 2,01,507 लोगों ने प्रशिक्षण लिया, जिनमें लगभग 78,000 महिलाएं थीं। National Cooperative Development Corporation (NCDC) ने महिला सहकारी समितियों को लगभग 5,715 करोड़ रुपए वितरित किए हैं, जिनसे 1.56 करोड़ से अधिक महिला शक्ति लाभान्वित हुई है।

उपसभाध्यक्ष महोदया, जन औषधि केंद्र आज गरीब व मध्यम वर्गीय परिवारों के स्वास्थ्य के सुविधा स्रोत बन रहे हैं। आज सहकारिता मंत्रालय PACS के माध्यम से जन औषधि केंद्रों को बढ़ावा दे रहा है, जिससे एक तरफ आम नागरिकों को बेहद सस्ती generic दवाइयों का लाभ मिल रहा है, वहीं ये PACS भी आर्थिक प्रगति का स्रोत बन रही हैं।

उपसभाध्यक्ष महोदया, सहकारिता को लेकर संविधान निर्माता भी कितने गंभीर थे, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकती हैं कि इसे संविधान के Fundamental Rights के अंतर्गत आर्टिकल 19 में दर्शाया गया है। Directive Principles of State Policy के 43बी और भारतीय संविधान के पार्ट बी में भी इसे निर्देशित किया गया है, क्योंकि पुरातन समय से ही भारत के आर्थिक विकास का ढाँचा सहकारिता पर निर्भर रहा है। इतिहास गवाह है कि जब भी देश पर कोई आर्थिक संकट आया, तो इन सहकारी समितियों ने आगे बढ़ कर देश को उस संकट से उबारने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सहकारिता सेक्टर ने निर्बल, निर्धन, गरीब, पीड़ित, शोषित लोगों के जीवन में बहुत अहम भूमिका निभाया है। जो लोग सिस्टम को नहीं समझते, उनके लिए एक-दूसरे की मदद करके, एक-दूसरे का हाथ पकड़ कर आगे बढ़ने का नाम ही सहकारिता है। सभी जानते हैं कि अमूल भी इसी आंदोलन से निकला है। आज dairy production व्यापार में अमूल ने एक अमिट छाप छोड़ी है। इसी क्षेत्र में मदर डेयरी भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। खादी को आज भारतीय सहकारी समितियों ने भारत में ही नहीं, बल्कि विश्व में भी उच्चतम शिखर पर पहुँचा दिया है। आज देश में 8 लाख से अधिक सहकारी समितियाँ हैं, जो कृषि, मत्स्य, डेयरी सहित न जाने कितने क्षेत्रों में काम कर रही हैं। अगर संख्या के हिसाब से देखें, तो आज हम विश्व के सबसे बड़े सहकारी समूहों में शामिल हैं। हर दूसरे घर का कोई न कोई सदस्य किसी न किसी रूप से सहकारिता से जुड़ा है।

उपसभाध्यक्ष महोदया, सहकारिता सिर्फ मुनाफा कमाने का साधन नहीं है, बल्कि मानवीयता के विकास का भी रास्ता है। भारतीय संस्कृति के साथ-साथ यह पारिवारिक व सामाजिक जीवन के विकास का भी मूल मंत्र है। यही कारण है कि आज भारत की सहकारिता क्षेत्र में 60 प्रतिशत भागीदारी है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकती हैं कि कृषि वितरण में 29 परसेंट, कृषि क्रेडिट में 30 परसेंट, उर्वरक वितरण में 35 परसेंट, उर्वरक उत्पादन में 25 परसेंट, चीनी उत्पादन में 35 परसेंट, दुग्ध उत्पादन में 15 परसेंट, गेहूँ उत्पादन में 13 परसेंट, दलहन में 20 परसेंट, मत्स्य उत्पादन में 21 परसेंट योगदान सहकारी क्षेत्र से आता है। उपसभाध्यक्ष महोदया, 2019-20 के एक आँकड़े के अनुसार डेयरी सहकारिता ने भारत में लगभग 4.80 करोड़ लीटर दूध लगभग 1.7 करोड़ सदस्यों से इकट्ठा किया है। इससे ही आप अंदाजा लगा सकती हैं कि सहकारिता कितने लोगों को प्रभावित कर रही है। इस सबके बावजूद, यूपीए सरकार ने इस क्षेत्र की हमेशा अनदेखी की, जिसके कारण स्टैंडर्ड मानकों, कौशल गुणवत्ता और professionalism की कमी से यह क्षेत्र पिछड़ता गया। आज सहकारी क्षेत्र ...(**समय की घंटी**)...

**उपसभाध्यक्ष(श्रीमती धर्मशीला गुप्ता)**: माननीय सदस्या, please conclude. आपका समय समाप्त हुआ। आपके पास 10 मिनट समय था। Please conclude.

**सुश्री इंदु बाला गोस्वामी**: आज सहकारी क्षेत्र भारत की ही नहीं, विश्व की अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जिसको ध्यान में रखते हुए आज जर्मनी, केन्या कोलंबिया और स्पेन में सहकारी विश्वविद्यालय बने हैं।

**उपसभाध्यक्ष (श्रीमती धर्मशीला गुप्ता)**: माननीय सदस्या, धन्यवाद। Please conclude.

**सुश्री इंदु बाला गोस्वामी**: त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक ...

**उपसभाध्यक्ष (श्रीमती धर्मशीला गुप्ता)**: आपका टाइम समाप्त हो गया।

**सुश्री इंदु बाला गोस्वामी**: मैडम, मेरे पास 15 मिनट का समय है।

**उपसभाध्यक्ष (श्रीमती धर्मशीला गुप्ता)**: आपके 10 मिनट्स ही थे। ...(**व्यवधान**)...

**सुश्री इंदु बाला गोस्वामी**: विधेयक, 2025 लाकर, मोदी सरकार ने ...

**उपसभाध्यक्ष (श्रीमती धर्मशीला गुप्ता)**: आपके 10 मिनट्स ही थे। ...(**व्यवधान**)... इसमें 10 मिनट ही लिखा हुआ है। ...(**व्यवधान**)... धन्यवाद। माननीय श्री जी.सी. चन्द्रशेखर। आपके पास 10 मिनट का समय है।

SHRI G.C. CHANDRASHEKHAR (Karnataka): Madam, I have 14 minutes.

**उपसभाध्यक्ष (श्रीमती धर्मशीला गुप्ता)**: यहाँ 10 मिनट ही लिखा हुआ है।

**श्री जी.सी. चन्द्रशेखरः** पार्टी के टोटल 31 मिनट्स हैं। Digvijaya Singhji spoke for 18 minutes. So, we are left with 14 minutes because he spoke for 18 minutes out of 31 minutes.

THE VICE-CHAIRPERSON (SHRIMATI DHARMSHILA GUPTA): Okay.

SHRI G.C. CHANDRASHEKHAR: Thank you, Madam, for having given me the opportunity to speak on the "Tribhuvan" Sahkari University Bill, 2025. This name,

Tribhuvan, is inspired by Tribhuvandas Patel, a great freedom fighter and key person in cooperative movement in India who founded Kaira District Cooperative Milk Producers' Union, or AMUL. He played a crucial role in mobilizing farmers against British monopoly. And also, Prime Minister Jawaharlal Nehru recognized the importance of cooperative model and supported its expansion and was committed to strengthening cooperative movement. He inaugurated Amul's first dairy plant in 1955. Cooperative institutions are not just money business, but symbols of regional pride and self-reliance. Same like Amul, I am proud to say in my State our Nandini Karnataka Milk Federation, KMF, is the second largest dairy cooperative in India. It started with just Rupees four crores in 1975, and today it has reached around Rs.27,000/- crores, with 15,210 village-level cooperative diaries, out of that, 4,340 cooperative dairies run exclusively by women --this is the women empowerment in rural area, Madam, -- where approximately 27 lakh farmers supply milk daily. Around one crore litres of milk is procured by the Government by giving around Rs.1,800/- crores of subsidy annually. Madam, why I mentioned 'Nandini' here, is because during the North East Cooperative Dairy Conclave in Guwahati, our Home Minister stated that five multi-city dairy cooperatives would be merged with Amul by advocating 'One Nation, One Society' to favour Amul. This is against the federal cooperative system of the country. A decision like this should not be encouraged. As much as AMUL is important to Gujarat, in the similar way, 'Nandini' is a pride of our 7 crores Kannadigas. At any cost, at any moment, we will not allow to merge 'Nandini' with any other society. For your kind information, Karnataka was the first State in the country to start the Agricultural Credit Cooperative Society in 1905 in a very small village called Kanaginahal of Gadag district under the leadership of Shri Siddanagouda Sanna Ramanagouda Patil who is recognized as the Father of Cooperative Movement in Karnataka. Madam, on this occasion, we have to remember the contribution of Dr. Verghese Kurien known as the Father of White Revolution. His contribution is remarkable.

Madam, now, I would like to mention some of my observations on the Bill. The Central Government will decide key positions like Vice Chancellor and Executive Board members. This could lead to political interference and reduce the University's independence. The Bill says, IRMA will remain independent, but in reality it will have to follow Central Government rules, which could limit its decision-making power. Madam, already the proposed changes to the University Grants Commission, UGC regulations affect the appointment process for University faculty and Vice-Chancellors. The new rules give Governors the exclusive power to appoint VCs,

replacing the current system where States form search committees. This takes away power from the elected State Governments and affects University's governance. We have already seen problems in States like Tamil Nadu, Kerala, and West Bengal. Madam, not only these States, in all over the country, the Governors are interfering in the University matters and appointing VCs and Registrars. It should not happen, Madam. These new rules lower the academic experience required for the VCs, allowing non-academic individuals to take leadership roles. A VC should be the academic leader, not a bureaucrat.

This will increase political interference. 'Education' is in the Concurrent List. So why should the institutions developed with State-funding and effort be controlled by the Centre? The University is being set up in Gujarat, while the States like Maharashtra, Kerala, Karnataka and Tamil Nadu, with strong cooperative sectors, are being ignored. The Bill does not guarantee opportunities for women, young people or tribal communities in cooperative education. The Bill does not say whether the University will be funded by the Government or private companies, raising concern of the financial stability. The Bill plans to merge around 284 cooperative training centres into the university. This may create financial stress and disrupt their current progress.

Madam, one system may not work for all. Different regions and different industries like dairy and fisheries have different cooperative needs. A single approach may not work everywhere. The Bill says, the university will train 8 lakh people every year, but there is no clarity or clear plan how it will be achieved and how they will give the jobs for those people. Many universities, especially, in Maharashtra and Kerala, already offer cooperative management courses. Instead of creating a new university, the Government should improve those existing programmes. The Bill talks about meeting global education standards but does not explain how it will work with international institutions or adopt global best practices.

Madam, 'cooperative' is a very big sector. Nearly 8 lakh societies are there in India and depositors and dependants are middle class and lower-middle class people but run by very big sharks. The scams will rarely come to light. In most of the cases, people will not get justice at all. For example, Madam in Karnataka, there are nearly 42,551 cooperative societies, out of which 25,035, nearly, 58.86 per cent are under profit and 14,498, nearly, 34.7 per cent are under loss. Madam, just to be more precise, I will give one example. In one Assembly Constituency in Karnataka, Bengaluru, known as Basavanagudi, there are five cooperative banks, namely, Guru Raghavendra Cooperative Bank, Vasista Cooperative Bank, *Souharda* Cooperative Bank, *Nagarathna* Cooperative Bank and *Guru* Sarva Bahuma Cooperative Bank. All

these five bank scams affected two lakh innocent depositor-families. Ninety per cent of the people deposited their retirement fund meant for their livelihood and healthcare. Due to this distress, many depositors lost their lives. Even though the State Government has given the cases to CBI, but CBI is not taking up the investigation to provide justice. Who will hear the cry of these common people, Madam?

Madam, I will say one thing. From these cooperative banks, most of the politicians -- irrespective of the political party, I am telling you -- and their relatives have taken the loan. It is not a small loan. It is of Rs. 100 crores-Rs. 150 crores. After 10-15 years, they have not paid even the interest. All this has accumulated, and they have also not paid back this money. Madam, now those people who have deposited, whether they are getting full money or not but, at least, these people who cheated the bank, who cheated those people, they have to be punished. I will urge the Government, through you, that it has to take necessary action against them. Madam, one part of the cooperative sector is suffering due to malfunction of the system.

Lastly, I quote, "*Sahkar Se Samruddhi*". I am telling you that this name is really very beautiful. For all the captions for the programmes' names, the BJP gives very fancy names, and they also market it very well. Whether these programmes will reach the people or not, but the names will become very famous. As you know, Madam, most of the programmes are not new programmes. It was there earlier also. They renamed, rebranded them. For example, 'National Manufacturing Policy' in 2011 became 'Make in India' in 2014; 'National e-Governance Plan' became 'Digital India' in 2015. '*Rastriya Swasthya Bima Yojana*' in 2008 became '*Ayushman Bharat*' in 2018. '*Nirmal Bharat Abhiyan*' in 2012 became '*Swachh Bharat Abhiyan*' in 2014. '*Rajiv Awas Yojana*' in 2009 became '*Pradhan Mantri Awas Yojana*' in 2015.

This Central Government gives only Rs.2 lakh to the State Government. The State Government gives Rs.5 lakh to each house. But, the State Government does not take the credit. The Central Government, by just giving Rs.2 lakh, is taking credit like anything. The State Government is giving Rs.5 lakh, but the Central Government is only giving Rs.2 lakh. On that, they are charging 18 per cent GST. Totally, they will collect 18 per cent on Rs.7 lakh which comes to around Rs.1,26,000 back. Thus, the Central Government's contribution will be only Rs.75 thousand.

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BIRENDRA PRASAD BAISHYA) *in the Chair.*]

But they are taking the credit like anything. This is the position how the BJP is taking the credit. The National Girl Child Day Programme has become *Beti Bachao, Beti Padhao*. They have just got the name changed. The situation has not got changed. From 2014 to 2022, approximately 2,99,520 rape cases were reported across India, as per the NCRB data. For the programme between 2014-15 to 2019-20, Rs.448 crores were allocated. In this, nearly 78.91 per cent just went for publicity purpose. Just imagine how they are spending money for publicity! सिर्फ नाम बदलने से क्या होगा? असली काम है, the programme has to reach the people, then only it will happen. This University should be useful to people; it should not for publicity sake. Protect the autonomy of the University, uphold federalism and respect the needs and aspirations of States because States and the Centre have to work hand in hand. The Centre should not take away the power from States; it is not correct. Since we are living in a federal system, the Centre has to support the State Government. Thank you very much.

SHRI MOHAMMED NADIMUL HAQUE (West Bengal): Sir, I rise today on behalf of the All India Trinamool Congress, to share my observations on the Tribhuvan Sahakari University Bill, 2025. This Bill, much like many of the Government's recent initiatives, is long on grand promises, but short on real solutions. We are being told that this University will revolutionise cooperative education and create employment. But, in reality, it does neither. Instead, it is yet another attempt by this Government to centralise power, divert resources from real priorities and mislead people with hollow assurances. Institute of Rural Management Anand, IRMA's, administrative and academic autonomy will be subjected to frameworks specified by the Union Government. The Bill's provisions might erode the work of the cooperative movement, which strives on decentralised and self-governing principles. If IRMA's autonomy can be overridden, it sets a precedent for other autonomous institutions to be similarly absorbed into centralised frameworks. The spirit of cooperatives has always been one of local autonomy and community-driven decision-making. Cooperatives thrive when farmers, small traders and local stakeholders are in control. But, time and again, this Government has shown its deep distrust of decentralised governance. From GST regime to the amendments to the cooperative banking laws and now with this Bill, the pattern is clear. The BJP Government wants to bring everything under the control of the Union, leaving no room for States or local bodies to make decisions. This Bill is yet another example of how cooperative federalism is being steadily dismantled and replaced with a command-and-control approach that

weakens the very institutions it claims to support. This Bill is one which was rushed through without sufficient consultation with key stakeholders. Moreover, what have you done on education? One out of three sanctioned Ekalavya schools is not functional. Funds for States like West Bengal are stopped because we do not accept the name PM-SHRI. In 2023, the Union Government was supposed to give Rs.1,750 crores to West Bengal under the Samagra Shiksha Mission. However, only Rs.310 crores have been released so far. The Union's expenditure on education has been 0.37 per cent of GDP. So, what is the use of setting a 6 per cent target in the New Education Policy? Over 5,000 teaching posts in the Central Universities are vacant. On the other hand, in Bengal, 47 lakh youth have received industry-orientated skill training under Utkarsh Bangla.

Ten lakh youths have been absorbed by the industry. One crore girl students have benefited from Kanyashree scheme. In 13 years, we have established 30 new universities and 24 new Government MBBS medical colleges. Four crore students have benefited under Aikyashree and one crore students have benefited under Shikshashree scholarships. Eighty thousand credit cards under the Student Credit Card Scheme and Rs.2,800 crore worth bank loans have been sanctioned. Our Party has always believed in strengthening co-operative institutions, while ensuring that their autonomy and regional character remain intact. If the Government is truly committed to establishing an independent institution that is free from political and bureaucratic interference, which is accountable to stakeholders rather than to the Union Government and genuinely focused on empowering co-operatives rather than controlling them, we are open to supporting this initiative. But, if this Bill is merely a tool to bring co-operatives under the centralised control, then we cannot and will not support it. The Government must make its stance clear whether it wants a university for the co-operatives or a university to control the co-operatives. That is my question.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BIRENDRA PRASAD BAISHYA): The next speaker is Shri R. Girirajan.

SHRI R. GIRIRAJAN (Tamil Nadu): Sir, before I start, I would like to put on record in this august House the humongous contribution made by our leader Dr. Kalaignar in the field of co-operative federal system in this country. No other leader in this country has done so much for the establishment and development of co-operative system to boost the life and nature of poor people in the country.

The title of the Bill should have been in English. Why to impose Hindi or Sanskrit unnecessarily even in naming of the Bill? The kind of Hindi imposition is not at all good for the country like India where unity in diversity is the backbone of the democratic nation. Do not break the backbone of our democracy.

The "Tribhuvan" Sahkari University Bill, 2025, is aimed to enhance the co-operative education, training, research, policy and development. This Bill sets the foundation for knowledge-driven globally competitive co-operative sector. At this juncture, I would like to say something regarding the UGC. The UGC is unnecessarily interfering with the functioning of the State Universities, including unnecessarily nominating persons to the Selection Committee for selecting Vice-Chancellors of State Universities. The UGC has no power to interfere with the State Universities ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BIRENDRA PRASAD BAISHYA): You can respond when your turn comes.

SHRI R. GIRIRAJAN: The co-operatives are the foundation of national development. The co-operatives are also the foundation of local self-government organisations. ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BIRENDRA PRASAD BAISHYA): Allow him to speak. Later, you can raise your issue.

SHRI R. GIRIRAJAN: As regards the foundation of national development of co-operative democracy, I can proudly say that the first co-operative society in the country was started in 1904 in a village called Thirur in the present Thiruvallur District of Tamil Nadu. I request that one more University should be set up in Tamil Nadu at Thirur where the first co-operative society was started in this country. The poor cannot do anything for their benefit on their own. They can succeed only if they make joint efforts. So, we emphasise the need for co-operatives.

There is a saying in Tamil, [&] "Only if people gather together and pull a chariot, the chariot will move." Today, the co-operative systems are operating in all sectors and farmers, dairy farmers, weavers, manufacturers, goat breeders, sugarcane

---

[&] English translation of the original speech delivered in Tamil.

growers, housing, village workers, fishermen and women, all sectors are forming their own co-operatives to protect their interests.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BIRENDRA PRASAD BAISHYA): Hon. Member, kindly try to conclude.

SHRI R. GIRIRAJAN: The co-operative movement played an important role in mixed economy... ...*(time-bell rings)*... I will take only one minute. Nearly 30,000 co-operative societies are functioning effectively in Tamil Nadu. The economy will be maintained and the democracy will be maintained if co-operatives thrive in this country. This movement should function according to the wishes of their members without political interference. Co-operative federal system is the fundamental principle of our Constitution. Our hon. Chief Minister, Thalapathy M.K. Stalin, has reiterated that if there is any disturbance to co-operative federalism, the Government and the people of Tamil Nadu will stand in front to oppose such move and save co-operative federalism in the country. Thank you, Sir.

DR. M. THAMBIDURAI: Sir, I have a point of order.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BIRENDRA PRASAD BAISHYA): Under which rule?

DR. M. THAMBIDURAI: Sir, give me one minute...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BIRENDRA PRASAD BAISHYA): Your point of order is under which rule? ...(*Interruptions*)...

DR. M. THAMBIDURAI: Sir, I want to say something...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BIRENDRA PRASAD BAISHYA): Hon. Member, kindly mention the rule first. ...(*Interruptions*)... Mention the rule under which you want to raise the point of order. ...(*Interruptions*)...

DR. M. THAMBIDURAI: *

---

* Not recorded.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BIRENDRA PRASAD BAISHYA): No, no. It is not going on record. ...(*Interruptions*)...Nothing is going on record. ...(*Interruptions*)... You are not mentioning the rule under which you want to speak. ...(*Interruptions*)... Nothing will go on record. Now, I would like to request hon. Member, Dr. Vikramjit Singh Sahney to speak on this Bill.

SHRI VIKRAMJIT SINGH SAHNEY (Punjab): Mr. Vice-Chairman, Sir, today, I rise to discuss the transformative power of cooperative movements, especially in the context of "सहकार से समृद्धि"। In a land where Gandhiji's methods found home, the cooperative sector has been not only the backbone of rural empowerment but has proven to be sustainable model for economic and social upliftment in our country. सर, हमें देखना होगा कि cooperative movements, जिसका आधार सहकार से समृद्धि तक है। यह सहकरिता से हमारे गरीब किसानों की, हाउसिंग कोऑपरेटिव की, गरीब लोगों का cooperative banks में पैसा जमा हुआ, उससे कितनी समृद्धि आई। What is cooperative? Cooperative is where individuals इकट्ठे होकर अपने रिसोर्सेज़ को पूल करके रिस्क शेयर करते हैं और collective strength से सबको बेनिफिट होता है। This ethos is evident across India where cooperatives have played a pivotal role in empowering farmers thereby boosting rural economy. India's cooperative movement is not merely an economic initiative; it is tied to social empowerment. हमारे देश में कई सेक्टर्स में cooperatives हैं, जिनके बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं - dairy farming, milk, agriculture cooperatives, housing cooperatives, cooperative banks in finance sector, textiles and rural credit are our primary rural societies. Cooperatives continue to face several challenges. Sir, generally, in cooperatives, we see lack of professional management, internal conflicts amongst Members coming from various backgrounds and very weak leadership. There is also an issue of transparency because these cooperatives do not come under the purview of institutions like Comptroller and Auditor General (CAG) or CVC. The issue of governance of our cooperatives is a big concern.

Sir, you will be surprised to note that while the age limit for a normal Government servant is 58 or 60 years, some of the CEOs of cooperatives can continue well into their 80s, highlighting a significant gap in governance. Despite the success stories, *sahkari* or cooperative movement faces various challenges.

Now, let us turn to today's topic, that is, Tribhuvan Sahkari University Bill, 2025. Amul, originating in Gujarat's Anand, stands as a beacon. त्रिभुवन दास पटेल जी ने, सरदार पटेल जी की गाइडेन्स में इसकी नींव रखी, लेकिन आज हम अपने कर्तव्यों का उल्लंघन करेंगे, अगर डॉ. वर्गीस कुरियन का नाम नहीं लेंगे, जिन्होंने 1946 में अमूल ब्रैंड को

आणंद में स्थापित किया, जिसमें आज 36 लाख farmers member हैं। मैं समझता हूं कि यह दुनिया का सबसे बड़ा कोऑपरेटिव है। इसका 60 हज़ार करोड़ रुपये तक का रेवेन्यू है। The Bill proposes establishment of 'Tribhuvan' Sahakari University. मैं समझता हूं कि ऐसी यूनिवर्सिटीज़, हमारी agrarian States, जिनमें पंजाब है, हरियाणा है, यूपी है, वहाँ पर ऐसे campus बनने चाहिए, ऐसी cooperative universities बननी चाहिए, ताकि हमारी dairy farming, हमारे किसान भाइयों, हमारी primary agriculture societies को मदद मिले।

महोदय, मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि cluster farming में बड़े cooperatives के साथ हमें छोटे cooperatives, पाँच-सात गाँवों को इकट्ठा करके, उनका एक cooperative cluster बनाया जाए, जहाँ पर किसान खुद ही अपने perishable goods की storage करे। किसान दाल, सरसों का तेल, आटे की चक्की, सभी कुछ, जो value addition है, उनको वहाँ पर cooperatives में करे, ताकि उसको अपनी फसल का सही दाम मिल सके।

महोदय, हम जो किसान की इन्कम डबल करना चाहते हैं, वह तभी संभव होगी, जब किसान value added cooperatives की तरह अपनी फसल को न बेचे, बल्कि वहीं पर value addition करे।

महोदय, एक प्वाइंट यह है कि agriculture credit societies बहुत कम हैं।हमारे देश में इनकी संख्या सिर्फ 12,000 है, जबकि हमारा लक्ष्य 2 लाख तक करने का है। यह कब और कैसे पूरा होगा - यह मैं गृह मंत्री जी, जो कोऑपरेटिव मिनिस्टर भी हैं, उनसे जानना चाहूंगा।

महोदय, यह बहुत अच्छी बात है कि इसका एक सेपरेट डिपार्टमेंट बना दिया गया है, इसलिए हमें one-district one-product one-cluster - महात्मा गाँधी जी का जो स्वराज का सपना था, हमें उसको पूरा करना होगा, ताकि हमारे देश में one-district one-product one-cluster का cooperative बने। हम इसकी उम्मीद करते हैं, लेकिन इसको सिर्फ गुजरात में बनाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि agrarian States में इसकी शाखाएं और इस university के campus भी होने चाहिए, ताकि यह सहकारी मूवमेंट घर-घर में फैलाया जा सके और सहकारिता में accountability एवं transparency लाई जा सके। उपसभाध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BIRENDRA PRASAD BAISHYA): Thank you. Now, hon. Member, Sivadasan ji.

DR. V. SIVADASAN (Kerala): Sir, the headquarters of the proposed University is suggested at Gujarat. The noted personality in the cooperative sector, Dr. Verghese Kurien, had also given immense contribution to the cooperative sector and to the nation, especially in Gujarat. But, he has been neglected by this Government. Sir, Dr. Kurien is known as the 'Father of White Revolution' in India. He was felicitated with various awards, including the World Food Prize in 1989. He has contributed

immensely to the cooperative sector and the IRMA. Still the Government completely sidelined him. It is shocking. I suggest the name of this University should be Tribhuvan-Kurien University. The cooperative sector of Kerala is an example of the success of democratic and decentralized cooperative network. The local autonomy is the key feature of cooperative movement. It is the strength of the cooperative sector and cooperative activities.

Sir, cooperatives function best when they are free to operate. A centralized University under this model will become a tool of political control of the Union Government. The Union Government is trying to destroy the cooperative movement where it is in the right path in letter and spirit. I am representing here the State of Kerala. Kerala's cooperative banks serve as the backbone of rural economy, providing financial support to the farmers, small traders and self-help groups. The Union Government is attacking them and the Right Wing is spreading the negative propaganda against our cooperative sector banks. They want to make way for private and corporate banking dominance which will benefit large financial institutions over small scale borrowers. The BJP-led Union Government has been pushing for the greater RBI control over our cooperative banks. They are reducing the powers of the State Government which violates the federal structure and the State's managing in managing the cooperative sector.

Cooperative sector is in the State List. But the Union Government is trying to grab the power of States. That is why they are intervening in this sector with wrong intention. In India, Kerala is one of the largest centres of cooperatives according to investment and diversity of activities. In cooperative sector, we have banks; we have dairy production units; we have hospitals; and we have transportation facilities. It is also involved in electricity generation. The network of cooperative banks in Kerala is an example of robust and popular banking network which is accessible to people. The protection and assistance of the Union Government is very necessary for the advancement of cooperative sector. The self-help attitude and togetherness of the people constitute the strength of cooperative sector. The base of the cooperative sector is the strong faith in each other. There is no wonder that those who are injecting the politics of venom are trying to destroy the cooperative sector. ...*(Time-bell rings.)*... Only one minute, Sir. The Union Government is trying to destroy the strong bond of the local communities and to centralise cooperative sector. In this Bill, there is only a nominal representation of the State with only four State or Union Territory representatives. This means that the University will be completely controlled

by the Union Government. This is against the basic principle of the cooperative movement.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BIRENDRA PRASAD BAISHYA): Hon. Member, try to conclude.

DR. V. SIVADASAN: Sir, give me 30 seconds. The Government should design the university in a democratic way. It should ensure that all the States have meaningful representation. The cooperative sector should be free from centralisation. The base, autonomy and decentralisation of cooperative sector should be protected. Thank you, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BIRENDRA PRASAD BAISHYA): Next speaker is hon. Member, Shri Babubhai Jesangbhai Desai.

**श्री बाबूभाई जेसंगभाई देसाई** (गुजरात): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं "त्रिभुवन" सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक, 2025 पर बोलने के खड़ा हुआ हूं। माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, आदरणीय मंत्रीगण और सम्मानित सदन के सदस्यगण, आज मैं इस महत्वपूर्ण "त्रिभुवन" सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक, 2025 के समर्थन में खड़ा हुआ हूं, जो हमारी शिक्षा व्यवस्था को एक नई दिशा और नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाला है। यह विधेयक केवल विश्वविद्यालय प्रशासन में बदलाव नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के सुनहरे भविष्य की नींव है। यह सरकार की दूरदर्शिता और शिक्षा के प्रति गहरी प्रतिबद्धता है।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय प्रधान मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि माननीय प्रधान मंत्री के दिल में 140 करोड़ जनता का दर्द है। इसीलिए माननीय प्रधान मंत्री जी ने युवा, नारी, गरीब और किसान - ये चार भारत के स्तम्भ रखे हैं। यह बिल इन चारों स्तम्भों को फायदा पहुंचाने वाला है। महोदय, शिक्षा समृद्धि का मूल आधार है। शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्त करने का माध्यम नहीं है, बल्कि राष्ट्र निर्माण और आर्थिक विकास का आधार भी है। कोई भी देश तब तक सशक्त नहीं बन सकता है, जब तक उसकी युवा शक्ति शिक्षित, सशक्त और आत्मनिर्भर न हो। इसी सोच के साथ हमारी सरकार ने "त्रिभुवन" सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक, 2025 को प्रस्तुत किया है, जिससे यह विश्वविद्यालय आधुनिक, नवाचार आधारित और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बन सके। माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सहकारिता मंत्री का बहुत-बहुत आभार मानता हूं कि यह विश्वविद्यालय हमारे गुजरात में आणंद में आ रहा है, इसीलिए सारे गुजरात की ओर से हम सहकारिता मंत्री का बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, गुजरात मॉडल से प्रेरणा उच्च शिक्षा की दिशा में एक क्रांति है। गुजरात जो आज विकास, नवाचार और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है, उसने शिक्षा के क्षेत्र में भी कई ऐतिहासिक सुधार किए हैं। गुजरात सरकार ने द्विस्तरीय विश्वविद्यालयों, स्टार्टअप

कल्चर और उद्योग आधारित शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देकर अपने युवाओं को रोजगार योग्य और नवाचार के लिए प्रेरित किया है।

इसी मॉडल से प्रेरणा लेकर त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक, 2025 को लाया गया है, जिससे यह संस्थान देश और विदेश के छात्रों के लिए एक प्रमुख शैक्षणिक केंद्र बन सके। माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, यह विधेयक त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय को शैक्षणिक और प्रशासनिक स्वायत्तता प्रदान करेगा, जिससे यह अपने निर्णय लेने में अधिक सक्षम होगा। नई निगरानी प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी, ताकि विश्वविद्यालय में अनियमितता को रोका जा सके।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, हमारे गुजरात में इस सहकारिता मॉडल के कारण गुजरात को एक मॉडल बोला जाता है। हमारे गुजरात में बनासकांठा में बनास डेयरी है, साबरकांठा में साबर डेयरी है, पंचमहल में पंचामृत डेयरी है, आणंद में अमूल डेयरी है और सूरत में सुमुल डेयरी है। देश में ऐसी अनेक cooperatives में चलने वाली हमारी सहकारी डेयरियाँ हैं। हमारी सहकारी डेयरियाँ गुजरात की सबसे बड़ी दूध उत्पादक हैं। ये सहकारी डेयरियाँ दूध मंडलियों और सहकारी मंडलियों के माध्यम से, किसानों को जो तकलीफ होती है, उसमें वे finance grant भी करती हैं और किसानों को बचा लेती हैं। जो दूध मंडलियाँ हैं, वे farmers को पशुपालन के लिए गाय और भैंस जैसे दूध वाले पशु खरीदने के लिए भी पैसा देती हैं।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, शिक्षा की गुणवत्ता के सुधार में तकनीकी शिक्षा, digital learning और कौशल विकास को प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि छात्र वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बन सकें। नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए छात्रों को विशेष अनुदान में सुविधा दी जाएगी। वित्तीय स्थिरता और वैश्विक सहयोग के माध्यम से त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय को अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों और उद्योग जगत के साथ जोड़ने के लिए विशेष योजनाएँ बनाई जाएँगी। निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे विश्वविद्यालय आत्मनिर्भर बन सके और शिक्षा का स्तर ऊँचा हो। छात्रों और शिक्षकों के लिए, व्यापक सुधार के लिए छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय छात्रवृत्ति, अनुसंधान अनुदान और स्टार्टअप प्रोत्साहन देने के लिए योजनाएँ बनाई गई हैं। योग्यता आधारित भर्ती प्रणाली लागू होगी, जिससे केवल सर्वश्रेष्ठ शिक्षक ही छात्रों को शिक्षित कर सके।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, नया भारत और नेपाल की दिशा में यह एक ऐतिहासिक कदम है। त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय केवल एक शैक्षणिक संस्थान नहीं है, बल्कि यह एक वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में परिवर्तन करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। जिस तरह गुजरात में शिक्षा और नवाचार में नए मानक स्थापित किए गए हैं, उसी तरह यह विधेयक नेपाल और भारत की शिक्षा व्यवस्था को एक नई ऊँचाई तक ले जाएगा। माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, सरकार की शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता है। हमारी सरकार का सपना है कि हर छात्र को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा मिले, जिससे वह सिर्फ एक डिग्रीधारी नहीं, बल्कि एक कुशल और आत्मनिर्भर नागरिक बन सके। यह विधेयक शिक्षा के माध्यम से आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और सामाजिक सशक्तीकरण को नई दिशा देगा।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, यह केवल एक विधेयक नहीं, बल्कि हमारी युवा शक्ति के उज्ज्वल भविष्य की नींव है। मैं सभी माननीय सदस्यों से अपील करता हूँ कि वे राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठ कर इस ऐतिहासिक विधेयक का समर्थन करें। हमारे प्रधान मंत्री जी का सूत्र है, आइए, हम 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' के मंत्र के साथ शिक्षा को नई ऊँचाई पर ले जाएँ।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, सहकारी क्षेत्र में बिखरे हुए शैक्षणिक ढाँचों को संबोधित करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। यह मोदी सरकार के व्यापक दृष्टिकोण 'सहकार से समृद्धि' के अनुरूप है। इस दिशा में सरकार ने 8 लाख से अधिक सहकारी संस्थाओं की क्षमता का पूर्ण उपयोग करने के लिए यूपीए सरकार के कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय से अलग एक स्वतंत्र सहकारिता मंत्रालय का गठन किया। इस क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों को सुनिश्चित और सुव्यवस्थित करने के लिए मोदी सरकार ने त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक, 2025 प्रस्तावित किया है, जिससे ग्रामीण प्रबंधन संस्थान, आणंद (IRMA) को एक विश्वविद्यालय का दर्जा देने का प्रयास किया गया है, ताकि सहकारी क्षेत्र में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता दी जाए।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, यह पहल तकनीकी और प्रबंध शिक्षा को सशक्त बनाने के लिए, अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करने के लिए, वैश्विक मानकों को पूरा करने के लिए, भाजपा नीत एनडीए सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप है। आत्मनिर्भर सहकारी समितियों के लिए दृष्टिकोण, प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी का अन्त्योदय का दृष्टिकोण, सहकारी संस्थाओं में आत्मनिर्भरता को रेखांकित करता है, जिससे उन्हें भारत के आर्थिक परिप्रेक्ष्य में केन्द्रीय भूमिका दी जा सके।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, पूर्ववर्ती यूपीए सरकार के दौरान, वित वर्ष 2013-14 में सहकारी संस्थाओं के लिए बजट आवंटन मात्र 122 करोड़ रुपये था, जिसके कारण ग्रामीण कारीगरों के लिए आवश्यक कार्यक्रमों को पर्याप्त वित्तीय सहायता नहीं मिल सकी और महाराष्ट्र में 101 सहकारी चीनी मिलें बंद हो गईं। इसके विपरीत, मोदी सरकार ने 2021 में एक स्वतंत्र सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की और इस क्षेत्र के लिए बजट को बढ़ाकर 1,183 करोड़ रुपये कर दिया, जो यूपीए सरकार के कार्यकाल के आवंटन का 9.7 गुना है।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, डेयरी सहकार योजना के अंतर्गत, डेयरी सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) के आधुनिकीकरण और क्षमता निर्माण के लिए 5,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो यूपीए सरकार द्वारा राष्ट्रीय डेयरी योजना में आवंटित राशि का दोगुना है। यह महत्वाकांक्षी विधेयक सरकार के इस सहकारी ढांचे को मजबूत कर हाशिए पर मौजूद समुदायों को सशक्त बनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मोदी सरकार द्वारा 'आत्मनिर्भर भारत' बनाने के लिए विशिष्ट शिक्षा को मजबूत करने और मुख्य क्षेत्रों के लिए विशिष्ट विश्वविद्यालयों की स्थापना करने से भारत के उच्च शिक्षा के परिपेक्ष्य का सक्रिय रूप से परिवर्तन हो रहा है। महोदय, त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय, जिसे IRMA के रूप में विकसित किया जाएगा, सहकारी क्षेत्र की शिक्षा पर केंद्रित होगा और सहकार से समृद्धि के दृष्टिकोण को सुदृढ़ करेगा। ठीक इसी प्रकार, जैसे

IRMA लंबे समय से 'अमूल' जैसी भारत की प्रमुख सहकारी संस्था को प्रतिभा में सहायता प्रदान करता है। इसी तरह गति शक्ति विश्वविद्यालय, परिवहन और लॉजिस्टिक के क्षेत्र में विशेषज्ञता को बढ़ावा दे रहा है, जबकि राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय आंतरिक सुरक्षा और पोलिसिंग अध्ययन को सशक्त बना रहा है। लद्दाख में स्थित सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय जलवायु विज्ञान, ऊर्जा और लोकनीति में अनुसंधान को आगे बढ़ा रहा है, जो इस क्षेत्र की विशिष्ट भौगोलिक चुनौतियों का समाधान करने में सहायक है।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, यह संस्थान केवल एक शैक्षणिक केंद्र ही नहीं है, बल्कि रोजगार सृजन का भी एक प्रमुख स्रोत है, जो छात्रों को विशिष्ट कौशल प्रदान कर, उन्हें भारत के आर्थिक और रणनीतिक क्षेत्रों में सीधे योगदान के लिए तैयार कर रहा है, जिससे उच्च गुणवत्ता वाले रोजगार के अवसर और क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित हो रहा है।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, सहकार को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय नीतिगत कार्यवान मोदी सरकार ने हमेशा विधायी और नीतिगत कार्यवाही आधारित शासन का समर्थन किया है। सरकार की यह दूरदृष्टि सहकारी क्षेत्र में भी परिलक्षित होती है। महोदय, मोदी सरकार ने वर्ष 2023 में बहु-राज्यीय सहकारी समिति अधिनियम, 2002 में संशोधन प्रस्तुत किया था, जिसका उद्देश्य सहकारी संस्थाओं में प्रशासन को सशक्त बनाना, पारदर्शिता बढ़ाना, जवाबदेही सुनिश्चित करना और चुनावी प्रक्रियाओं में सुधार लाना था। माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मोदी सरकार ने वर्तमान विधेयक के माध्यम से देश में सहकारी आंदोलन के संस्थाओं को एक नेटवर्क के माध्यम से मजबूत करने का प्रयास किया है। प्रस्तावित सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ, सहकारी क्षेत्र में कुशल कार्यबल की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित होगी।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, क्षमता निर्माण पर इस विशेष ध्यान से न केवल तकनीकी दक्षता में वृद्धि होगी, बल्कि यह हाशिए पर मौजूद वर्गों को सशक्त बनाते हुए उन्हें सहकारी शासन में अधिक भागीदारी का अवसर प्रदान करेगा। मैं मानव संसाधन में निवेश के माध्यम से सहकारी समितियों की क्षमता के संबंध में बताना चाहता हूँ कि वित्त वर्ष 2024-25 के केंद्रीय बजट में भारत की जनसांख्यिकीय संपदा का लाभ उठाने और अमृत पीढ़ी को सक्षम बना कर विकसित भारत, 2047 की मजबूत नींव रखने पर विशेष बल दिया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सहकारी क्षेत्र भी अमृत काल के लाभों का पूरा लाभ उठा सके, मोदी सरकार राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद (एनसीसीटी) और वैकुंठ मेहता राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान जैसी पहलों पर कार्य कर रही है। ये संस्थान डेयरी प्रबंधन, ग्रामीण उद्यमिता और डिजिटल साक्षरता जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को कवर करने वाले लक्षित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, 2022-23 में 2,01,000 से अधिक व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया, जिसमें महिलाओं की उल्लेखनीय भागीदारी रही। एनसीसीटी ने 2023-24 में 3,619 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए, जो अपने निर्धारित लक्ष्य 1,740 से कहीं अधिक थे। क्षमता निर्माण के प्रति इस प्रतिबद्धता से सहकारी क्षेत्र में कुशल पेशेवरों की सतत आपूर्ति सुनिश्चित होती है।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, प्रस्तावित सहकारी विश्वविद्यालय इस प्रयास को और अधिक सशक्त बनाएगा, जिससे हाशिए पर मौजूद समुदायों को सक्षम बना कर सहकारी शासन में उनकी भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा और एक अधिक समावेशी आर्थिक परिदृश्य का निर्माण होगा।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' का मंत्र सहकारिता की रीढ़ के रूप में है। मोदी सरकार ने सहकारी क्षेत्र में हाशिए पर मौजूद समुदायों, विशेष रूप से अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के समावेश को उल्लेखनीय रूप से बढ़ावा दिया है। वंचित इकाई समूह और वर्ग की आर्थिक सहायता योजना (VISVAS) समान भागीदारी सुनिश्चित करने वाली सहकारी समितियों की स्थापना या विस्तार करने के लिए अनुसूचित जाति, ओबीसी और सफाई कर्मचारियों जैसे हाशिए पर रहने वाले समूह को वित्त सहायता प्रदान करती है। ...(**समय की घंटी**)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BIRENDRA PRASAD BAISHYA): You have taken enough time. It is time to conclude.

**श्री बाबूभाई जेसंगभाई देसाईः** माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मेरा सहकार मंत्री से यह विनती है कि मैं गोपालक समाज से आता हूँ...

**उपसभाध्यक्ष (श्री बीरेन्द्र प्रसाद बैश्य)ः** आपको काफी समय मिला है, अब आप conclude कीजिए।

**श्री बाबूभाई जेसंगभाई देसाईः** चूँकि हमारी गोपालक मंडलियों को मताधिकार से वंचित किया गया है, इसलिए मैं मंत्री जी से यह आग्रह करता हूँ कि उसके बारे में अच्छी तरह से सोचा जाए, धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BIRENDRA PRASAD BAISHYA): The next speaker is hon. Member, Shrimati Sagarika Ghose.

SHRIMATI SAGARIKA GHOSE (West Bengal): Respected Mr. Vice-Chairman, Sir, on behalf of All India Trinamool Congress, I rise to speak on the "*Tribhuvan*" Sahkari University Bill, 2025, which seeks to establish the Institute of Rural Management Anand (IRMA) as "*Tribhuvan*" Sahkari University or India's first national cooperative university.The Government has suddenly remembered the enormous contributions that IRMA and the cooperative movements have played in Gujarat. But why is the Modi Government trying to rewrite history? The recognition of respected Shri Tribhuvandas Patel is good. But, in full-page advertisements released by Amul, there is one glaring omission. Why is the Government reluctant to honour the giant, who

founded IRMA in 1979, built and nurtured IRMA and whose legacy shaped Amul in the Milk Revolution in Gujarat in India? I refer here, Sir, to India's milkman, father of India's White Revolution and founder of IRMA, Dr. Verghese Kurien. Why is Dr. Verghese Kurien's name missing from this university? Why? The reason why this Government is not recognizing a pioneering son of India and dedicated servant of the people like Dr. Verghese Kurien is because he never became part of the BJP ecosystem. Dr. Kurien staunchly believed that if universities have to become excellent, they need to be above all, autonomous. In his lifetime, he had been outspoken on refusing to let the BJP Government meddle with IRMA.

6.00 P.M.

Sir, I ask a question to this Government: Is the Government finding it difficult to give due credit to Dr. Kurien ¥ Is that the reason this Government not honouring Dr. Verghese Kurien? ¥

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BIRENDRA PRASAD BAISHYA): Hon. Members...

SHRIMATI SAGARIKA GHOSE: Yes, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BIRENDRA PRASAD BAISHYA): It is now 6.00 p.m. If the House agrees, we may sit beyond 6.00 p.m. today till the disposal of the"Tribhuvan" Sahkari University Bill, 2025. Do I have leave of the House to extend sitting beyond 6.00 p.m.?

SOME HON. MEMBERS: Yes, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BIRENDRA PRASAD BAISHYA): So, the House will continue now.

SHRIMATI SAGARIKA GHOSE: ¥Of the 54,000 educational institutions run by Christians, about 75 per cent of those students are non-Christian. They are Hindus, they are Muslims, they are Jains, they are Sikhs. Instead of targeting minorities, when

---

¥ Not recorded as directed by the Chair.

will we learn to acknowledge their stellar contribution in all walks of our national life? Gujarat was Dr. Verghese Kurian's *karmabhoomi*. He lived all his life in Anand, building 17 major institutions, including the NDP or National Dairy Development Board. But, what did the BJP do? ¥How very sad, Sir! How very sad! Shri Tribhuvandas Patel set up the Kaira District Cooperative Milk Producers' Union. But, who changed the destiny of milk cooperatives? ...(*Interruptions*)... Who brought all milk cooperatives together? Who helped set up Anand Milk Union Limited (AMUL)? It was Verghese Kurien.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BIRENDRA PRASAD BAISHYA): Kindly authenticate.

SHRIMATI SAGARIKA GHOSE: Sir, Amul ushered in an economic and social revolution. 'One line, one can, one vote', said Dr. Kurien.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BIRENDRA PRASAD BAISHYA): Kindly authenticate.

SHRIMATI SAGARIKA GHOSE: All milk producers, irrespective of caste and creed, stand in one line, pour milk into one can and each would have a vote. That was the egalitarianism. The milk revolution was a revolution in egalitarianism and social equality.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BIRENDRA PRASAD BAISHYA): Kindly authenticate your allegation.

SHRIMATI SAGARIKA GHOSE: It was Varghese Kurien who resigned from the Indian Institute of Management, Ahmadabad because he did not believe that Government subsidies should go to training managers who would then work abroad in multinational corporations. He founded the concept of the "barefoot manager". He created the concept of "rural management". That is how IRMA was born. It is a brainchild of Dr. Verghese Kurien. The respected Mr. Tribhuvandas Patel and Dr. Kurien enjoyed a father-son relationship. Sir, today Dr. Verghese Kurien's daughter calls Tribhuvandas Patel '*kaka*'. 'Tribhuvan *kaka*', is what she calls him. They had a father-son bond. It was Tribhuvandas Patel who pleaded with Dr. Kurien to stay on in Anand and build the Milk Cooperative with new technologies, new machines. History

---

¥ Not recorded as directed by the Chair.

did not start in 2014, Sir. The Cooperative movement was built decades before Narendra Modi*ji* became Chief Minister of Gujarat. There is a long line of the great Nehruvian nation builders like Dr. Verghese Kurien, Dr. Manmohan Singh that this Government cannot bring itself to credit and acknowledge. This Government has an antipathy to the great Nehruvian nation builders like Dr. Kurien. But this antipathy and hostility to the Nehruvian nation builders must not get the better of good sense. Dr. Kurien founded IRMA and, as a proud son of Gujarat, Dr. Verghese Kurien's name must find place in this new University.

(MR. CHAIRMAN *in the Chair.*)

MR. CHAIRMAN: Your time is over.

SHRIMATI SAGARIKA GHOSE: Sir, they are trying to rewrite history but those who try to rewrite history will never be forgiven by history. History will never forgive those who rewrite history. Thank you, Sir.

MR. CHAIRMAN: Thank you.

**श्री रामचंद्र जांगड़ा** (हरियाणा)ः सर, मेरा एक प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है।

MR. CHAIRMAN: Yes.

**श्री रामचंद्र जांगड़ा:** सर, यह नियम 238क से संबंधित है।

MR. CHAIRMAN: Yes, go ahead.

**श्री रामचंद्र जांगड़ा:** सर, माननीय सदस्या ने इस कोऑपरेटिव बिल को minority और majority के साथ जोड़ा है कि वर्गीज़ कुरियन को इसलिए ignore किया गया, क्योंकि वे minority class से हैं। यह सरासर गलत है। नियम 238क में कहा गया है, "कोई सदस्य किसी अन्य सदस्य या लोक सभा के किसी सदस्य के विरुद्ध मानहानिकारक या अपराध में फंसाने वाले स्वरूप का कोई आरोप नहीं लगायेगा जब तक कि आरोप लगाने वाने सदस्य ने सभापति और संबंधित मंत्री को भी इसकी पूर्व सूचना न दी हो ताकि मंत्री उत्तर दिये जाने के प्रयोजन के लिए इस विषय की जांच कर सके।" सभापति जी, इसको delete करना चाहिए।

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, whether this House can reflect on the conduct of persons who are not Members of this House, there is a detailed ruling given by the Chair. I will examine it in that perspective. It is on two-fold situations: If there is anything which is inculpating the person or incriminating the person, then, the mechanism is different; if it is an assertion of a factual situation, then, it is different. The matter will be examined.

**श्री प्रफुल्ल पटेल** (महाराष्ट्र): सभापति महोदय, आज मैं त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी बिल, 2025 पर चर्चा करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। महोदय, मैं इस बिल का पूरी तरह से समर्थन करते हुए एक जानकारी आपके माध्यम से सदन को देना चाहता हूँ और बड़े गर्व के साथ देना चाहता हूँ कि त्रिभुवनदास पटेल, जो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट मिल्क प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव के संस्थापक रहे, हमारे पूर्वज भी वहीं से आते हैं, जहां से त्रिभुवनदास जी ने शुरुआत की। सर, जो आणंद शहर है, मेरी पत्नी भी वहीं से आती हैं।

**श्री सभापतिः** आपने यह कह कर बहुत आनंदित किया है, क्योंकि उनके द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में मैं गया था। She was a towering figure and you were only assisting. मैं आपके इलाके में गया था, वह बड़ा अच्छा कार्यक्रम था।

**श्री प्रफुल्ल पटेलः** बड़ी गम्भीर चर्चा हो रही थी, कुछ लोग नाराज़ हो रहे थे, तो मैंने सोचा कि ज़रा मूड बदलने का काम किया जाए। हमारे मित्र जयराम जी भी थोड़ा मुस्कुरा दें।

**श्री सभापति**: तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अक्सर हाउस में रहा करें।

**श्री प्रफुल्ल पटेलः** तो हाउस हमेशा प्रफुल्लित रहेगा। सर, एक जानकारी और भी बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे सदस्यों ने इस बिल पर चर्चा की। अमूल नाम कैसे आया? आणंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, इसलिए अमूल उसका शॉर्ट फॉर्म है। हम लोग अमूल बटर, अमूल की बात करते हैं। बहुत सारे लोग जानते नहीं होंगे, इसलिए मैंने सोचा कि पूर्वज वहाँ से आए, तो इतनी जानकारी तो मेरे पास होनी चाहिए और मुझे इसे साझा करने की भी यहाँ कोशिश करनी चाहिए।

सर, यह जो बिल है और जो इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट, आणंद की बात हो रही है। नो डाउट, यह एक बहुत अच्छी संस्था है। उस संस्था का एक स्वरूप, आज के आधुनिक युग में, कोऑपरेटिव सहकारिता के महत्व को और बढ़ाने के लिए है। प्रधान मंत्री जी का लक्ष्य है - "सहकार से समृद्धि" - यह एक बहुत ही नेक लक्ष्य है, और इसे आगे और भी सशक्त बनाने की ज़रूरत है। यह बिल उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

यह जो हमारा कोऑपरेटिव क्षेत्र है, नो डाउट, हम अमूल की बात करते हैं। वहाँ से लाखों परिवारों के जीवन में उन्नति और परिवर्तन आया, खासकर महिलाओं के माध्यम से आया। क्योंकि

जो दूध का उत्पादन करने वाले हैं, उनमें ९९ प्रतिशत महिलाएँ ही इस धंधे से जुड़ी रही हैं। उन्होंने अपने परिवार को अधिक आय का एक साधन इस कोऑपरेटिव मूवमेंट के माध्यम से प्रदान किया।

त्रिभुवनदास पटेल जी की जो बात यहाँ हुई, नो डाउट, वर्गीस कुरियन साहब का योगदान भी कहीं से कम नहीं समझना चाहिए। लेकिन अगर कोई महान व्यक्ति और वह भी स्वतंत्रता सेनानी हैं...

उसके बाद जिन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल के आदेश पर गुजरात में इतनी बड़ी कोऑपरेटिव मूवमेंट की शुरुआत की, अगर उनका नाम इस यूनिवर्सिटी को दिया जाता है, तो उसका हमें सहर्ष स्वागत करना चाहिए। मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि यह जो कदम है, वह लोगों को अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करेगा। जहां तक हमारे कुछ साथी डॉ. वर्गीस कुरियन की बात कर रहे थे, नो डाउट, उनके बारे में किसी के मन में कोई प्रश्न चिन्ह नहीं होना चाहिए। उन्होंने इस देश के किसानों और खासकर दूध उत्पादन के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया। उसको भी कहीं किसी को नजरअंदाज करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि हमारे राष्ट्र ने उनको कई बार सम्मानित किया है और अवश्य ऐसा कहीं न कहीं मौका आएगा, जो उनका और भी सम्मान किसी न किसी माध्यम से जरूर होगा। आज कोऑपरेटिव क्षेत्र में, क्योंकि मैं महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ हूं, गुजरात में हमारे पूर्वज थे, मगर महाराष्ट्र और गुजरात, खासकर ये दोनों जो राज्य हैं, ये बहुत ही ...(**व्यवधान**)...

**श्री सभापति**: आपका कार्यक्षेत्र महाराष्ट्र से आगे और प्रांतों में भी है।

**श्री प्रफुल्ल पटेल**: जी, सर।

**श्री सभापति**: तो आप महाराष्ट्र तक सीमित क्यों हो रहे हैं?

**श्री प्रफुल्ल पटेल**: सर, मैंने कोऑपरेटिव क्षेत्र के मामले में कहा। हमारे भाई दिग्विजय जी ने भी पहले अपने भाषण में यह बात दोहरायी थी कि महाराष्ट्र और गुजरात ने इस क्षेत्र में काफी पहल की थी। अब पूरे देश में चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, अन्य राज्य हों या आपका प्रांत राजस्थान हो, सभी जगहों पर आज कोऑपरेटिव का एक बहुत बड़ा जाल फैला हुआ है। कोऑपरेटिव अब कुछ लिमिटेड दायरे में नहीं, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में आज उसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। पहले एक जमाना था कि हमारे महाराष्ट्र में हम लोग कहते थे कि कोऑपरेटिव मतलब शुगर फैक्टरी है, शक्कर कारखाना है, बस वही एक कोऑपरेटिव है, ऐसा नहीं है। दूध संघ है, वही कोऑपरेटिव है, ऐसा नहीं है। आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि कॉटन ग्रोइंग में हमारा स्टेट काफी बड़ा है। आज कोऑपरेटिव क्षेत्र में इतनी सारी टेक्स्टाइल्स की spinning और weaving mills का हमारे यहां निर्माण हो गया है। आज हमारे वहां पर Inland fisheries में कोऑपरेटिव क्षेत्र में बहुत बड़ा प्रगति का काम हुआ है। आज कृषि क्षेत्र में Farmer Producer Organisation हो, अन्य जो भी हमारी कोऑपरेटिव संस्था है, उसके माध्यम से लाखों और करोड़ों लोगों को अपना जीवन बदलने का एक मौका मिला है। आज जंगल कामगारों के लिए, जो वन में

काम करते हैं, जैसे ओडिशा में काम करते हैं, छत्तीसगढ़ में काम करते हैं, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में वन कामगारों की भी कोऑपरेटिव सोसायटीज़ हैं और उनको भी वन उपज के माध्यम से चाहे महुआ फ्लावर हो, तेंदुपत्ता हो और बाकी बहुत सारे उत्पादन को कोऑपरेटिव क्षेत्र के माध्यम से बढ़ा रहे हैं। आज बैंकिंग में एक बात निश्चित है। कुछ अपवाद, इधर-उधर की घटनाएं, दुर्घटनाएं, बैंकिंग क्षेत्र में, कोऑपरेटिव में हुई होंगी, लेकिन आज अगर आप मोटा-मोटी देखें, तो जो बैंकिंग की reach है, चाहे nationalized banks हों या प्राइवेट बैंक्स हो, उनका जाल पूरे देश में नजर आता है। आज भी ऐसा कोई गांव नहीं बचा होगा, जहां पर बैंकिंग की जरूरत हो और बैंक न पहुंची हो और अगर वहां बैंक पहुंची है, तो केवल कोऑपरेटिव बैंक पहुंची होगी। यह बहुत जरूरी है और इसी वजह से आज यह जो बिल है, इसमें खाली यूनिवर्सिटी तो एक माध्यम है, यूनिवर्सिटी के माध्यम से लोगों को अच्छी ट्रेनिंग मिले, वहां से अच्छे मैनजमेंट के ग्रेजुएट्स तैयार हों, वहां पर जाकर फैकल्टी उनको नई-नई techniques सिखाए। सर केवल नाम के लिए कोऑपरेटिव है, लेकिन साथ-साथ आज आधुनिक युग में उनके लिए sky is the limit. उस वजह से उनको अगर नई techniques, नई चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है, तो उसका हम लोगों को सहर्ष स्वागत करना चाहिए। यह जो बिल है, वह कोऑपरेटिव क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए, हमारे देश में नई पीढ़ी को नई दिशा देने के लिए, क्योंकि नई पीढ़ी मैनेजमेंट में बाकी चीज़ों में चली जाती है। कोई फाइनेंस में चला जाएगा, कोई टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जाता है, लेकिन रूरल मैनेजमेंट के क्षेत्र में नई पीढ़ी को आकर्षित करने के लिए किया जाता है, जिसके माध्यम से अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं, अपने भविष्य को बना सकते हैं।

यह भी इस बिल का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। मैं इस वजह से इस बिल का पूरी तरह से समर्थन करते हुए पुनश्चः सरकार को भी बधाई दूंगा कि त्रिभुवन दास पटेल, जिन्हें गुजरात में 'त्रिभुवन काका' भी कहते हैं, हर व्यक्ति उनका सम्मान करता है। हमारे नरहरी भाई और मेरे, हम दोनों के पूर्वज एक ही जिले के हैं, इसलिए नरहरी भाई को भी मालूम है कि पूरा गुजरात 'त्रिभुवन काका' के नाम से त्रिभुवन दास पटेल के योगदान को बहुत महत्व देता है, अतः मैं सरकार को बहुत-बहुत बधाई देते हुए इसका पुरज़ोर समर्थन करता हूं।

---

## RECOMMENDATIONS OF THE BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, I have to inform that the Business Advisory Committee in its meeting held on the 1st of April, 2025 has allotted time for Government legislative business as follows:

| | |
|---|---|
| 1. Consideration and passing of the Immigration and Foreigners Bill, 2025, as passed by Lok Sabha. | **Five hours.** |

2. Consideration and passing of the following Bills after they are considered and passed by Lok Sabha:-